



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 9 नवम्बर, 2006/18 कार्तिक, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 9 नवम्बर, 2006

संख्या पीसीएच-एचए(2)8/99-29976-33376.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 100 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायतों को, मोबाईल सर्विस प्रोवाइडर पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ, मोबाईल संचार टावर स्थापित करने के लिए चार हजार रुपये प्रति टावर की दर से शुल्क और दो हजार रुपये

प्रतिवर्ष की दर से, प्रति टावर वार्षिक नवीकरण फीस उद्गृहीत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

- (i) नवीकरण फीस के एकमुश्त संदाय के लिए पांच वर्षों के ब्लाकों (खण्डों) में विकल्प दिख जा सकेगा (पांच वर्षों के लिए नवीकरण फीस सहित पूर्ण रकम के आगामी संदाय के लिए चालीस प्रतिशत छूट के साथ)।
- (ii) नवीकरण फीस में प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् पच्चीस प्रतिशत की नियत कालिक बढ़ौतरी होगी।
- (iii) प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना, जो उसी टावर से सांझा है, के लिए साठ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त रकम उद्गृहीत की जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
राजित (पंचायती राज)।

[Authoritative English text of this Department notification No. PCH-HA(2)8/99, dated 9th November, 2006, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 9th November, 2006

No. PCH-HA(2)8/99-26576-29976.—In exercise of the powers conferred under clause (d) of sub-section (1) of section 100 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise the Gram Panchayats to levy duty on the Mobile Communication Service providers, for installation of Mobile Communication Tower at the rate of Rs. 4,000/- per tower and annual renewal fee at the rate of Rs. 2000/- per annum per tower with the following conditions:—

- (i) An option for lump sum payment of renewal fee may be given in blocks of 5 years (with 40% discount for upfront payment of the entire amount including renewal fees for 5 years).
- (ii) There shall be periodic increase in renewal fee by 25% after every 5 years.
- (iii) An additional amount at the rate of 60% shall be levied for every additional antenna which shares the same tower.

By order,
Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 नवम्बर, 2006/18 कार्तिक, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171 002, 14 सितम्बर, 2006

संख्या हिप्रविआ/421.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ), (ज), (झ), (घ) तथा (यच), सहपठित धारा 32 की उप-धारा (3), धारा 36, धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), धारा 40 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) तथा धारा 61 व 62 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य

सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

विनियम

भाग-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण, चक्रण व मध्यवर्ती सुविधाओं के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उद्गृहीत की जाने वाली फीसों एवं प्रभार) विनियम, 2006 है।

(2) भाग-II में अन्तर्विष्ट विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत पारेषण एवं चक्रण के कारबार में लगे व्यक्तियों को लागू होंगे तथा भाग-III में अन्तर्विष्ट विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुश्रवणित व सेवित एवं राज्य ग्रिड प्रणाली से जुड़ी अन्तराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादक कम्पनियों को लागू होंगे वाक्यांश “अन्तराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों” में सभी पारेषण, वितरण एवं व्यापार अनुज्ञप्तिधारी भी आते हैं।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) अभिप्रेत है;

(ख) “पहुंच अनुबन्ध” से विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा आवेदक के बीच अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली तक उपयोग के लिए खुली पहुंच के लिए किया गया अनुबन्ध अभिप्रेत है ;

(ग) पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध में किसी नियत अवधि के लिए “उपलब्धता” का अभिप्राय उस अवधि के दौरान, जिसमें पारेषण प्रणाली अपनी रेटिड वोल्टेज (Rated Voltage) पर विद्युत का पारेषण करने में समर्थ है, के घण्टों से है तथा उसे नियत अवधि में, कुल घण्टों की प्रतिशतता में अभिव्यक्त किया जाएगा;

(घ) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) “कारबार संचालन विनियम” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(च) “ग्रिड कोड” से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा अधिनियम की धारा 172 के खण्ड (ख) के अधीन अनुमोदित समझा गया राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है ;

- (छ) “अनुज्ञप्ति” से अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है तथा इसमें इस प्रयोजनार्थ समझी गई अनुज्ञप्ति भी सम्मिलित है ;
- (ज) “अनुज्ञप्तिधारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है या जिसे अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा गया है;
- (झ) “दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली का लाभ ले रहा है या लाभ लेने का इच्छुक हो;
- (ञ) “अन्य कारबार” से अनुज्ञप्त कारबार के अलावा पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अन्य कारबार अभिप्रेत है;
- (ट) “लघुकालिक पारेषण ग्राहक” से दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक के अलावा अन्य पारेषण ग्राहक अभिप्रेत है; तथा
- (ठ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

(2) शब्दों तथा पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो कि उनके लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं।

भाग—II

पारेषण, चक्रण तथा मध्यवर्ती सुविधा प्रभार

3. बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ अवधारण.—इन विनियमों में कोई बात विनिर्दिष्ट होते हुए भी, आयोग टैरिफ को अंगीकार करेगा, बशर्त कि ऐसा टैरिफ केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अवधारित किया गया हो।

4. पारेषण/चक्रण प्रभारों के अवधारण हेतु आवर्तिता.—(1) जब तक आयोग बहु वर्ष टैरिफ सिद्धान्तों को आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों तथा टैरिफ अवधारण के सिद्धान्तों के अनुसार अंगिकार नहीं करता है, किसी अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रभारों का अवधारण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और साधारणतया एक वर्ष में एक से अधिक बार उसे संशोधित नहीं किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधधीन, किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमत प्रभार, अनुज्ञेय राजस्व तथा निर्धारित व्यय, यदि आयोग संतुष्ट हो कि वास्तव में वसूल राशि में आधिक्य या कम किए गए व्ययों के लिए समायोजन आवश्यक तथा उचित है, अनुवर्ती अवधि के लिए नियत किए जाने वाले किन्हीं प्रभारों में समायोजन के अधधीन होंगे।

5. पारेषण/चक्रण प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी 30 नवम्बर को या उससे पूर्व आयोग को, वार्षिक आधार पर, या आयोग द्वारा चाहे जाने पर बारंबार, पारेषण प्रभारों या चक्रण प्रभारों के अवधारण हेतु, कारबार संचालन विनियमों में यथाकथित कार्यविधि का सम्यक् रूप में अनुसरण करते हुए, याचिका प्रस्तुत करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी को याचिका के साथ आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ हेतु आवेदन दायर करने के लिए मानदण्ड एवं आरूप (फारमेट)) विनियम, 2005 में दिए गए प्रारूप पर जानकारी संलग्न करनी होगी। पूर्ववर्ती अवधि (यों) की जानकारियां अंकेक्षित लेखों पर आधारित होनी चाहिए तथा जिस अवधि के अंकेक्षित लेखे उपलब्ध नहीं हैं, उस अवधि के अनांकेक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाने चाहिए :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारियां प्रस्तुत न करने की दशा में आयोग, यदि ऐसा करना चाहे तो, प्रभारों के अन्वधारण हेतु स्व-पेरणा से कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

(3) पारेषण प्रभारों या चक्रण प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका में, प्रस्तावित की गई या प्रस्तावित की जाने वाली प्रत्येक लागत मद, जो वार्षिक राजस्व अपेक्षा में सम्मिलित है, का विस्तृत औचित्य अन्तर्विष्ट होगा।

6. आयोग के आदेश.—(1) आयोग, याचिका के निपटारे हेतु, जैसे उपयुक्त समझे, अनुज्ञप्तिधारी को और जानकारियां, विशिष्टियां, प्रलेख, जनाभिलेख आदि, प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(2) आयोग, याचिका-कर्ता द्वारा दिये गए औचित्य, याचिका के सम्बन्ध में आपत्तियों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को, यदि कोई आयोग द्वारा मांगी गई हों, ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का विश्लेषण करेगा तथा विवेकी लागत व राजस्व मदों पर किए गए या किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का निर्धारण करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के 120 दिनों के भीतर, आयोग कारबार के संचालन विनियमों के अनुसार टैरिफ अन्वधारण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात् पारेषण प्रभारों या चक्रण प्रभारों से सम्बन्धित आदेश जारी करेगा।

7. पारेषण/चक्रण प्रभारों का प्रकाशन.—अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के आदेश में दिए गए समय के अन्दर-अन्दर अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिन में से एक हिन्दी भाषा का तथा एक अंग्रेजी भाषा का हो, प्रभारों से सम्बन्धित प्रमुख तत्त्व प्रकाशित करेगा। आयोग द्वारा इस प्रकार अवधारित प्रभार आयोग के आदेश में दी गई तारीख से प्रभावी होंगे तथा जब तक आयोग परिवर्तन अथवा उपांतरण सहित उसके उत्तरकालावधि में लागू रहने के लिए अनुज्ञप्त नहीं करता है, आयोग द्वारा अवधारित प्रभार प्रवर्तन में नहीं रहेंगे।

8. आदेश का सम्प्रेषण.—आयोग, आदेश जारी किए जाने के सात दिन के भीतर, आदेश की एक प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों को भिजवाएगा। आयोग कथित आदेश की, कारबार के संचालन विनियमों के विनियम 24 के उप-विनियम (9) में यथा-विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को, प्रति उपलब्ध करवाएगा।

9. अधिक राशि का प्रतिदाय.—अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा यथा अवधारित प्रभार वसूल करेगा। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित से अधिक प्रभार वसूल करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिक वसूली गई राशि उस व्यक्ति, जिसने अधिक प्रभारों का संदाय किया है, को भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित लघुकालिक मूल उधारदान दर के समतुल्य ब्याज सहित लौटानी होगी।

10. पूर्ण पारेषण प्रभार वसूल किए जाने के लिए लक्ष्य उपलब्धता.—पूर्ण पारेषण प्रभार वसूल किए जाने के लिए लक्ष्य उपलब्धता निम्नवत होगी :

(1) प्रत्यावर्ती धारा (ए. सी.) प्रणाली : 98 प्रतिशत

(2) उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) द्वि-खम्भायोजन तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा बैक-टू-बैक स्टेशन (Back to Back Stations) : 95 प्रतिशत

टिप्पणी 1.—स्थाई प्रभारों की लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से कम वसूली यथानुपात आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई भी प्रभार संदेय नहीं होंगे।

टिप्पणी 2.—लक्ष्य उपलब्धता, उपबन्ध—“क” में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, संगणित की जाएगी।

11. सकल वार्षिक राजस्व अपेक्षाएं.—विद्युत के पारेषण या चक्रण के लिए प्रभारों में निम्नलिखित मदों से युक्त वार्षिक पारेषण या चक्रण प्रभार की वसूली समाविष्ट होगी:—

- (क) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- (ख) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त पोषण परिव्यय;
- (ग) अवक्षयण;
- (घ) साम्या पर प्रतिफल;
- (ङ) कामकाजी पूंजी पर ब्याज;

परन्तु यह कि जब तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपयोगिता का हिस्सा है, राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता कारबार व राज्य भार प्रेषण केन्द्र (रा.भा.प्रे.के.) कारबार के लिए पृथक से लागत गदों की सूचना प्रस्तुत करेगी।

12. परिचालन एवं अनुरक्षण लागत.—(1) परिचालन एवं अनुरक्षण लागत में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

- (क) वेतन, मजदूरी तथा अन्य कर्मचारी व्यय;
- (ख) मुरम्मत एवं अनुरक्षण;
- (ग) प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय; तथा
- (घ) अन्य विविध व्ययों जैसे कि विधिक प्रभार, अंकेक्षण शुल्क, पट्टा प्रभार, किराया, उप-कर व कर इत्यादि।

(2) प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका में अनुज्ञातिधारी पूर्ववर्ती वर्ष तथा चालू वर्ष में किए गए परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय के ब्यौरे के साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए पूर्ण विस्तार में तथा उपयुक्त औचित्य के साथ प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि प्रणाली में संभरण हेतु सुधार लाने के लिए पहल करने हेतु या विशिष्ट कमियों आदि को दूर करने हेतु अनुज्ञातिधारी वर्ष के दौरान अनुमोदित परिचालन मूल्य तथा अनुरक्षण लागत से ऊपर अतिरिक्त राशि के समावेश का प्रस्ताव रख सकता है। यह प्रस्ताव विशिष्ट आवश्यकताओं के विस्तृत औचित्य

के साथ समर्थित होना चाहिए और ऐसा कोई भी प्रस्ताव आयोग द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(3) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी (रियों) के परामर्श से, नेटवर्क के अनुरक्षण एवं रख-रखाव में जानबूझकर कम खर्च करने के सुरक्षण के प्रति नियमित आधार पर परिसम्पत्ति अवस्था निर्धारण करने के लिए रचनातन्त्र को अन्तिम रूप देगा । इसे सुकर बनाने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को परिसम्पत्ति पंजिका बनाने को अन्तिम रूप देना आवश्यक होगा ।

13. परिसम्पत्ति आधार.—(1) आयोग वित्तीय वर्ष के आरम्भ में परिसम्पत्ति आधार अवधारण करेगा, जो—

- क (i) योजनाओं की वास्तविक सम्पूरित लागत, जो ऐसे आदेश में अनुमोदित से कम है, के लिए;
- (ii) योजनाओं या उनके पूर्ण न हुए भाग की लागत के लिए;
- (iii) कतिपय अनियंत्रणीय कारणों जैसे कानून या नीतियों में बदलाव, किसी आपात् स्थिति से निपटने आदि के कारण शुरू की गई पर्याप्त औचित्य से समर्थित योजनाओं के लिए;

समायोजित करते हुए पूर्ववर्ती आदेश में अनुमोदित परिसम्पत्ति आधार और —

- ख (क) योजनाओं, जिनके लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है; (ख) योजनाओं, जो आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा चुकी हैं, तथा (ग) योजनाओं, जिनके लिए आयोग का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है;
- को आवृत करते हुए वर्ष के दौरान प्रत्याशित पूंजीकृत किए जाने की सीमा तक प्रस्तावित विनिधान योजना के योग में से —

ग वर्ष के दौरान निवृत्त की जाने वाली प्रस्तावित परि-सम्पत्तियां, घटा कर होगा ।

(2) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा साम्या पर प्रतिफल का परिकलन, उप-विनियम (1) के अधीन यथापरिकलित परिसम्पत्ति आधार में शामिल की गई योजनाओं की लागत के वित्तपोषण के आधार पर किया जाएगा ।

14. ऋण पूंजी पर ब्याज.—(1) ऋण पूंजी पर ब्याज परिसम्पत्ति आधार के लिए अनुमोदित ऋणों पर ऋण-वार परिकलित किया जाएगा । प्रत्येक ऋण के लिए किसी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋण बकाया का निर्धारण सकल ऋण में से संचित प्रतिसंदाय को घटा कर किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि किसी बदलाव के परिणामस्वरूप उपयोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों में वृद्धि हो, तो वित्त पोषण में, जिसमें ब्याज दर, अधिस्थगन अवधि, उधार अवधि, संदाय अनुसूची इत्यादि भी आती है, किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि ब्याज लागत अनुसूचित बैंक की मूल उधारदान दर (पी0 एल0 आर0) के साथ पूर्वावधारित सीमा (मार्जिन) को, जो उस दर को यथार्थतः परावर्त करे जिस पर अनुज्ञप्तिधारी बाजार में ऋण ले सके, से जोड़ा जाएगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, वित्तीय प्रबन्धन जैसे कि निम्नतर ब्याज लागत अग्रग ऋणों से अदला बदली करके, अथवा कोई अन्य वित्तीय पुनर्संरचना इत्यादि द्वारा ब्याज लागत में कमी करने का हर सम्भव प्रयास करेगा तथा इन प्रयासों से होने वाली हितलाभ में भागीदारी एक तिहाई उपयोक्ता एक तिहाई अनुज्ञप्तिधारी तथा एक तिहाई आकस्मिकता आरक्षित निधि के अनुपात में होगी। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे हितलाभ की, आयोग को इसके अनुमोदन हेतु, संगणना प्रस्तुत करेगा।

(3) विदेशी मुद्रा ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान तथा वास्तविक ऋण प्रतिसंदाय पर सम्बन्धित वर्ष में विदेश मुद्रा विनियम दर में परिवर्तन के कारण रुपये के अन्तर की देयता ग्राह्य होगी, बशर्ते कि यह देयता सीधे ऐसी विदेश मुद्रा विनियम दर में परिवर्तन से उदभूत हुई है और यह अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ता या ठेकेदार के कारण न हुई हो।

15. अवक्षयण.— (1) अवक्षयण निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा—

- (क) अवक्षयण वित्तीय वर्ष के आरम्भ में स्थिर परिसम्पत्ति के मूल मूल्य पर संगणित किया जाएगा ;
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष अवक्षयण हेतु केन्द्रीय आयोग द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार संगणित राशि उपलब्ध करवायेगा;
- (ग) अवक्षयण परिसम्पत्ति को काम में लाने के प्रथम वर्ष से प्रभारित किया जाएगा। यदि परिसम्पत्ति का उपयोग वर्ष के किसी अंश के लिए होता है, तो अवक्षयण यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में यथानिर्दिष्ट, केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित अवक्षयण दरें, ऐसे समुचित उपान्तरण सहित जो विनियामक मंच अधिकथित करे, वितरण को भी लागू होगी।

16. साम्या पर प्रतिफल.— (1) साम्या पर प्रतिफल का परिकलन समादत्त साम्यापूँजी पर किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए समय-समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा अधिसूचित कर-पश्ची (Post tax) होगा।

(2) वितरण के लिए आयोग, समुचित उपान्तरण सहित, केन्द्रीय आयोग द्वारा पारेषण के लिए साम्या पर प्रतिफल की अधिसूचित दरें अंगीकार कर सकेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंशपूँजी तथा मुक्त आरक्षितियों, यदि कोई हों, से सृजित आन्तरिक संसाधनों का निवेश जारी करते समय वर्धित अधिमूल्य को भी साम्या पर प्रतिफल के परिकलन के प्रयोजन से समादत्त पूँजी ही माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों का वास्तविक उपयोग परिसम्पत्ति आधार में पूँजीगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(4) विदेश मुद्रा में साम्या निवेश पर उसी मुद्रा में विहित सीमा तक प्रतिफल अनुमत किया जाएगा और इसका प्रदाय देयक की नियत तिथि को प्रचलित विनियम दर पर भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

17. कामकाजी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज.—(1) कामकाजी पूंजी में सम्मिलित होगा —

(क) एक माह का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(ख) वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धित इतिहासिक लागत की 1 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; तथा

(ग) लक्ष्य उपलब्धता स्तर या चक्रण प्रभारों पर संगणित दो महीने के पारेषण प्रभारों के बराबर प्राप्तियां ।

(2) कामकाजी पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा पारेषण प्रभारों के अवधारण की तारीख को यथा लागू भारतीय स्टेट बैंक की लघुकालिक मूल उधारदान दर के समतुल्य होगी। यह होते हुए भी कि अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाह्य एजेन्सी से कामकाजी पूंजी ऋण नहीं लिया है, कामकाजी पूंजी पर ब्याज मानकीय आधार पर संदेय होगा ।

18. देयता-साम्या अनुपात.—(1) पारेषण प्रभार अवधारण हेतु, सभी परियोजनाओं के लिए, देयता-साम्या अनुपात (Debt Equity Ratio) केन्द्रीय आयोग के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ हेतु निर्बन्धन एवं शर्तों) विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट होगा;

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार संगणित देयता-साम्या राशि का प्रयोग ऋणों पर ब्याज, साम्या पर प्रतिफल तथा विदेश विनिमय दर में फेरफार के परिकलन के लिए किया जाएगा।

19. अन्य आय.—अनुज्ञप्तिधारी की निम्नलिखित स्रोतों से उद्भूत समस्त आय, अनुज्ञप्तिधारी की अन्य आय मानी जाएगी :—

(क) उन निवेशों, जो आकस्मिकता आरक्षित को वापस विनियोजित न किए गए हों, से ब्याज आय,

(ख) अन्य निवेशों, स्थिर तथा मांग जमा व बैंक में अतिशेष, से ब्याज आय,

(ग) किराये;

(घ) अनुज्ञप्त कारबार से अन्य कारबार, यदि कोई हो, से आय;

(ङ) विद्युत कारबार से अनुषंगी कोई अन्य आय ।

20. शुद्ध वार्षिक राजस्व अपेक्षा.—अनुज्ञप्तिधारी की वसूली योग्य शुद्ध वार्षिक राजस्व अपेक्षा का अवधारण, विनियम 11 के अधीन अवधारित सकल वार्षिक राजस्व अपेक्षा में से विनियम 19 के अनुसार अवधारित अन्य आय को कम करने के पश्चात् किया जाएगा ।

21. चक्रण प्रभार.—वितरण प्रणाली के उपयोक्ताओं द्वारा संदेय चक्रण प्रभारों का अवधारण निम्नलिखित सूत्रानुसार किया जाएगा :—

चक्रण प्रभार = $\frac{11 \text{ केवी तथा उससे ऊपर की वितरण प्रणाली की लागत}}{\text{आगामी टैरिफ कालावधि में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस के नेटवर्क में प्रक्षेपित विक्रय इकाइयां (युनिट) तथा चक्रित इकाइयाँ (युनिट):}}$

परन्तु यह कि जब कभी राज्य में खुली पहुंच को प्रोत्साहन देना आवश्यक तथा समीचीन लगे तो आयोग, आदेशद्वारा, इस विनियम के अधीन संगणित चक्रण प्रभारों के लिए ऊपरी सीमा नियत कर सकेगा।

22. पारेषण प्रभार—(1) दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभार निम्नलिखित सूत्रानुसार अवधारित किए जाएंगे :—

$$\text{“एमएलटीसी” (MLTC)} = \{[(\text{पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की शुद्ध वार्षिक राजस्व अपेक्षा (Net ARR of the Transmission Licensee)} / 12) - 0.75 * \text{एसटीआई (STI)} - \text{आईटीएफआई (ITFI)}] / \text{टीसीएल (TCL)}_{\text{एलटी (LT)}}\} * \text{सीएल (CL)}$$

व्याख्या—इस विनियम के प्रयोजनार्थ—

- (क) “एमएलटीसी” (MLTC) का अभिप्राय रुपयों/माह में मासिक दीर्घकालिक पारेषण प्रभार से है;
- (ख) “शुद्ध वार्षिक राजस्व अपेक्षा” (Net ARR) का अभिप्राय विनियम 20 में यथावधारित शुद्ध वार्षिक राजस्व अपेक्षा से है;
- (ग) “एसटीआई” (STI) का अभिप्राय उप-विनियम (2) के अधीन अवधारित माह के लिए पारेषण नेटवर्क के लघुकालिक ग्राहकों से आय से है;
- (घ) “आईटीएफआई” (ITFI) का अभिप्राय विनियम 23 के अधीन अवधारित माह के लिए मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं से आय से है ;
- (ङ) “सीएल”(CL) का अभिप्राय दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक द्वारा पारेषण प्रणाली की संवेदित क्षमता से है ;
- (च) “टीसीएल एलटी” (TCL_LT) का अभिप्राय सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों द्वारा पारेषण प्रणाली की कुल संवेदित क्षमता से है:

परन्तु यह कि जब कभी राज्य में खुली पहुंच को प्रोत्साहन देना आवश्यक तथा समीचीन लगे, तो आयोग, आदेशद्वारा, इस उप-विनियम के अधीन संगणित पारेषण प्रभारों के लिए ऊपरी सीमा नियत कर सकेगा।

(2) लघुकालिक पारेषण ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभारों का अवधारण हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2005 में यथाविनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

$$\text{ST_RATE} = 0.25 \times [\text{TSC}/\text{AV_CAP}]/365$$

व्याख्या—इस विनियम के प्रयोजनार्थ—

- (क) “ST_RATE” से लघुकालिक खुली पहुंच ग्राहक के लिए रुपयों में प्रति मेगावाट (MW) प्रतिदिन की दर अभिप्रेत है; तथा ST_RATE का अवधारण और प्रयोग राज्य पारेषण उपयोगिता, या अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, की पारेषण प्रणाली, जो अन्य अन्तराज्यिक पारेषण प्रणाली का भाग है, के लिए किया जाएगा;
- (ख) “TSC” से आयोग द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार अथवा वार्षिक राजस्व अपेक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "AV_CAP" से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी की अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली द्वारा निर्वाहित मेगावाट (MW) में औसत क्षमता अभिप्रेत है और यह पारेषण प्रणाली से संयोजित उत्पादन क्षमता तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा प्रतिपादित अन्य दीर्घकालिक संव्यवहार की संवेदित क्षमता का जोड़ होगी ।

(3) असंकुलित पारेषण गलियारे की दशा में लघुकालिक ग्राहक द्वारा पारेषण प्रभार निम्नानुसार उदग्रहित होंगे, अर्थात्—

(क) एक गुट में एक दिन में 6 घण्टे तक = (ST_RATE) का 1/4 भाग

(ख) एक गुट में एक दिन में 6 घण्टे से अधिक और 12 घण्टे तक = (ST_RATE) का 1/2 भाग

(ग) एक गुट में एक दिन में 12 घण्टे से अधिक और 24 घण्टे तक = (ST_RATE) के बराबर

(4) यदि पारेषण प्रणाली राज्य पारेषण उपयोगिता की हो, तो अंतःराज्यिक प्रणाली के उपयोग के लिए लघुकालिक ग्राहकों से वसूल किए गए प्रभार का 25 प्रतिशत राज्य पारेषण उपयोगिता अपने पास रखेगी और अतिशेष को दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा देय पारेषण प्रभारों को घटाने में समायोजित किया जाएगा ।

23. मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के लिए प्रभार— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मध्यवर्ती पारेषण सुविधा, यदि कोई है, के लिए ऐसी दरें व प्रभार होंगे जो अनुज्ञप्तिधारी और ऐसी सुविधाओं के उपयोक्ता के बीच सहमति से तय की जाएं :

परन्तु यह कि तय दरें व प्रभार उचित और युक्तियुक्त होंगे और पारेषण सुविधाओं के उपयोग के अनुपात में आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) इन मामलों पर पारस्परिक सहमति पक्षकारों के सर्वाधिक हित में होगी । यदि ऐसी सहमति यथोचित समयावधि में नहीं हो पाती है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन अवधारण हेतु आयोग को निवेदन करने का हकदार होगा और आयोग इस आशय का साक्ष्य चाहेगा कि समझौता-वार्ता नेक-नीयती से सम्पन्न हुई है और आपसी सहमति के लिए सभी यथोचित प्रयास किए जा चुके हैं ।

(3) यदि अधिनियम की धारा 35 के अधीन यथा उपबन्धित उपलब्ध अधिशिष्ट क्षमता के परिमाण के बारे में कोई वास्तविक विवाद उद्भूत होता है, तो पक्षकार आयोग को निवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।

(4) आयोग को, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व रखने वाले या परिचालन करने वाले किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को उसके पास उपलब्ध अधिशिष्ट क्षमता के परिमाण तक उनके उपयोग की व्यवस्था करने हेतु आदेश देने के लिए आवेदन किया जाएगा ।

(5) सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित उप-विनियम (4) के अधीन किसी आदेश के दिए जाने पर अपनी मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएं अधिनियम की धारा 36 के अधीन पारस्परिक सहमति से तय हुई दरों, प्रभारों और निबन्धनों व शर्तों पर, उपलब्ध करेगा ।

24. विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए प्रभारों की प्रयोज्यता— (1) पारेषित ऊर्जा के परिमाण व अवस्थिति को ध्यान में न रखते हुए चक्रण प्रभार सभी उपयोक्ताओं के लिए समान रूप से लागू किए जाएंगे ।

(2) खुली पहुंच वर्ग के आधार पर, अर्थात् लघुकालिक अथवा दीर्घकालिक पारेषित ऊर्जा के परिमाण के अवस्थिति को ध्यान में न रखते हुए पारेषण प्रभार सभी उपयोक्तताओं को समान रूप से लागू किए जाएंगे।

25. पारेषण प्रभार प्रोत्साहन.—(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विनियम 10 के अनुसार लक्ष्य उपलब्धता से परे वार्षिक उपलब्धता प्राप्त कर लेने पर, निम्नसूत्रानुसार प्रोत्साहन के लिए हकदार होगा —

$$\text{प्रोत्साहन} = \frac{\text{वार्षिक पारेषण प्रभार} \times [\text{प्राप्त की गई वार्षिक उपलब्धता} - \text{लक्ष्य उपलब्धता}]}{\text{लक्ष्य उपलब्धता}}$$

व्याख्या.—इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, प्रत्यावर्ती धारा (एसी) प्रणाली के लिए 99.75 प्रतिशत, तथा उच्च वोल्टेज डिष्ट धारा (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए 98.5 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता पर कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा। प्रोत्साहन में दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की वर्ष के लिए उनकी पारेषण व क्षमता के औसत आबंटन के अनुपात में हिस्सेदारी होगी।

26. पारेषण एवं वितरण क्षति का आबंटन.— विद्युत पारेषण एवं वितरण में ऊर्जा क्षति आबंटन हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रति सहायिकी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, प्रति सहायिकी की चरणबद्धता) विनियम, 2006 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

भाग—III

राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभार

27. राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभार का उद्ग्रहण एवं संग्रहण:—(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपना वित्तीय लेखा तथा किए गए व्ययों का लेखा पृथक से, संधारित करेगा। यदि राज्य पारेषण उपयोगिता राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चला रही है, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्बन्धित लेखों का संधारण राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा पृथक से किया जाएगा।

(2) राज्य ग्रिड से जुड़ने वाली इच्छुक उत्पादन कम्पनियां एवं अनुज्ञप्तिधारियों, जो अन्तःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं, को अपना आवेदन उपाबन्ध—'ख' पर दिए गए प्रपत्र में, राज्य ग्रिड से संयोजन की प्रस्तावित तारीख से न्यूनतम एक महीने पूर्व राज्य भार प्रेषण केन्द्र को एक लाख रुपये के शुल्क सहित देना होगा।

(3) वर्तमान में राज्य ग्रिड प्रणाली से जुड़ी हुई उत्पादन कम्पनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों, जो अन्तःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत हैं, को इन विनियमों के लागू होने की तारीख से एक माह की समय अवधि में उपरोक्त शुल्क सहित आवेदन करके राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पंजीयन कराना होगा।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्राप्त आवेदन का परीक्षण करने पर एवं आवेदन में दी गई सूचना को परिपूर्ण एवं सही पाये जाने पर, आवेदक को स्वीकरण के बारे में सम्यक् रूप से सूचित करते हुए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अभिलेखों में आवेदन को पंजीकृत करेगा तथा एक प्रति आयोग को प्रस्तुत करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ग्रिड से जुड़ी उत्पादन कम्पनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों, जो अन्तःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत अनुश्रवणित एवं सेवित हैं, से सम्बन्धित जानकारी आयोग को प्रत्येक वर्ष की 15 नवम्बर तक प्रस्तुत करेगा।

(5) अंतःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था हेतु कार्यरत उत्पादन कम्पनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण विनियम 11 में यथावर्णित व्यय तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य प्रासंगिक व्यय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(6) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार लघुकालिक खुली पहुंच ग्राहक को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को परिचालन प्रभार भी देने होंगे।

28. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संग्रहण का आधार.—राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वार्षिक अपेक्षा का अवधारण विनियम 20 में वर्णित वार्षिक राजस्व अपेक्षा संगणनाओं के अनुसार किया जाएगा और इसे पहले दो समान भागों में बांटा जाएगा, यथा, प्रथम जिसकी वसूली उत्पादन कम्पनियों से की जानी है एवं द्वितीय जिसकी वसूली अंतःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों से की जानी है। उसके पश्चात् प्रत्येक उत्पादन कम्पनी से वसूली योग्य प्रभारों का आबंटन स्थापित उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। अंतःराज्यिक विद्युत पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य प्रभारों का आबंटन पारेषण नेटवर्क से चक्रित ऊर्जा मात्रा पर आधारित होगा।

29. शुल्क एवं प्रभार अवधारण हेतु आवेदन.—(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक वर्ष, 30 नवम्बर तक आयोग को, आगामी वर्ष के लिए शुल्कों व प्रभारों के अवधारण हेतु, उपबन्ध—“ग” में दिए गए प्रपत्रों पर तथा आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग [टैरिफ हेतु आवेदन दायर करने के लिए मानदण्ड एवं आरूप (फॉरमेट)] विनियम, 2005 में उपबन्धों के अनुसार आवेदन/याचिका प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूलनीय “शुल्क एवं प्रभार” अवधारण हेतु आवेदन एक लाख रुपये के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियोजन प्रस्ताव तैयार करना होगा जिसमें नियोजन हेतु स्रोतों की जानकारी दर्शानी होगी। यह नियोजन प्रस्ताव प्रति वर्ष अद्यतन रूप से आयोग को उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) यदि चालू शुल्क एवं प्रभार पर आधारित संभावित राजस्व एवं आगामी वर्ष की राजस्व अपेक्षाओं में अन्तर परिलक्षित हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य राजस्व अन्तर को घटाने हेतु सुझाव देगा।

(5) आयोग आवेदन पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में, यदि कोई हो, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है, तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक स्पष्टीकरण देगा।

30. उत्पादन कम्पनियों एवं अंतःराज्यिक पारेषण व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों को जानकारी की उपलब्धता.—(1) आयोग को प्रस्तुत स्पष्टीकरण के पश्चात्, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पूर्ण आवेदन की एवं तथा अग्रेतर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की पूर्ण प्रतियां अंतःराज्यिक विद्युत पारेषण के अन्तर्गत कार्यरत उत्पादन कम्पनियों को उपलब्ध करवायेगा।

(2) शुल्क एवं प्रभार अवधारण हेतु आवेदन की राज्य भार केन्द्र की वेबसाईट पर डाउनलोड करने योग्य प्रपत्रों पर समस्त साझेदारों की जानकारी हेतु सुलभ उपलब्धता होनी चाहिए।

31. सुनवाई.—आयोग विशिष्ट कारणों के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत राजस्व गणना तथा शुल्क एवं प्रभार निर्धारण के प्रस्ताव पर कार्यवाही करेगा तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों, अन्तराज्यिक विद्युत पारेषण के अन्तर्गत कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों और ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें आयोग ऐसे राजस्व गणना तथा शुल्क एवं प्रभार अवधारण प्रस्तावों पर निर्णय लेने के परिपक्ष्य में उचित समझे, की सुनवाई करेगा।

32. आयोग के आदेश.—(1) आयोग, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए औचित्य, याचिका के सम्बन्ध में आपत्तियों तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी को, यदि कोई आयोग द्वारा मांगी गई हो, ध्यान में रखते हुए राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दी गई याचिका का विश्लेषण करेगा तथा विवेकी लागत व राजस्व मदों पर दिए गए या किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय का निर्धारण करेगा।

(2) आयोग राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने के 120 दिन के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उद्ग्रहित शुल्कों एवं प्रभारों के अवधारण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात् आदेश जारी करेगा। आयोग द्वारा इस प्रकार अवधारित शुल्क एवं प्रभार आयोग के आदेश में दी गई तारीख से प्रभावी होंगे तथा जब तक आयोग परिवर्तन अथवा उपान्तरण सहित उसके उत्तर-कालावधि में लागू रहने के लिए अनुज्ञात नहीं करता है, आयोग द्वारा अवधारित शुल्क एवं प्रभार प्रवर्तन में नहीं रहेंगे।

33. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण.—(1) उत्पादन कम्पनियाँ एवं अनुज्ञप्तिधारी, जो राज्य में अन्तराज्यिक विद्युत पारेषण के अन्तर्गत कार्यरत हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वार्षिक प्रभारों का भुगतान अग्रिम रूप से मासिक किस्तों में करेंगे।

(2) यदि भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो अवशेष राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्बन्धित शुल्कों के भुगतान सम्बन्धी विलम्ब अथवा भुगतान न किए जाने की दशा में विवादों का निराकरण यथासम्भव आपसी समझौता वार्ता के माध्यम से किया जाएगा। आपसी समझौता वार्ता से विवादों का निराकरण 90 दिनों के अन्दर न होने की दशा में, प्रकरण याचिका के माध्यम से आयोग के समक्ष किसी भी पक्षकार द्वारा निराकरण हेतु लाया जा सकेगा। आयोग द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

34. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन.—(1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र अथवा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अधधीन रहते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अधिनियम की धारा 40 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) और धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश दे सकता है, जिन्हें वह पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझे और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी निर्देशों का पालन करेगा।

(2) आयोग, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दाखिल आवेदन पर और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सुनवाई करने के बाद अगर संतुष्ट है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निरंतर रूप से पारेषण प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखने में विफल रहा है तो वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों पर जैसा आयोग

निर्णय ले ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के प्रचालन का नियंत्रण अपने पास लेने का निर्देश जारी कर सकता है ।

(3) उप-विनियम (1) और (2) के अधीन निर्देश, किसी अन्य कार्यवाई, जो अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा ।

भाग-IV

प्रकीर्ण

35. संशोधन की शक्ति.—आयोग, किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को परिवर्धित, परिवर्तित, बदल, उपांतरित या संशोधित कर सकेगा ।

36. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ.—यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या इसे किए गए आवेदन पर ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी कर अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व निभाने की बाबत, निर्देशित करने का अधिकार होगा, जो अधिनियम से असंगत न हो और आयोग के मतानुसार कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो ।

37. आदेश व दिशा निर्देश जारी करना.—अधिनियम तथा इन विनियमों के अध्याधीन रहते हुए, आयोग समय-समय पर इन विनियमों को क्रियान्वित करने तथा ऐसे क्रियान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि व उस से प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों पर आदेश तथा पद्धति निदेश दे सकेगा ।

38. निर्वचन.—इन विनियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवादक आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे तथा उन विवादकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

39. विविध.—(1) इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश, जो न्याय हित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोषों को रोकने के लिए आवश्यक हों, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) यदि आयोग को किसी मामले या मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायसंगत और समीचीन लगता है, तो इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के उपबन्धों में, किसी से विसांवादी प्रक्रिया, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, अपनाने से नहीं रोकेंगी ।

(3) इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) के अन्तर्गत जिनके सम्बन्ध में कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, कार्यवाही करने या शक्तियों को प्रयोग में लाने से अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से बाधित नहीं करेगी और आयोग ऐसे मामलों में उन शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन, जैसे वह उचित समझे, कर सकेगा ।

आयोग की आज्ञा द्वारा,
हस्ताक्षरित/—

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ।

उपाबन्ध-क

{विनियम 10 देखें}

पारेषण प्रणाली उपलब्धता संगणना प्रक्रिया

(1) उपलब्धता की संगणना तथा घोषणा प्रत्येक वोल्टेज स्तर के लिये पृथकतया की जाएगी।

(2) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की संगणना के प्रयोजन हेतु, पारेषण अवयवों को निम्न प्रवर्गों में समूहित किया जाएगा:—

(क) प्रत्यावर्ती धारा AC पारेषण लाईन: प्रत्यावर्ती धारा (AC) पारेषण लाईन का प्रत्येक परिपथ (circuit) एक अवयव माना जाएगा।

(ख) अन्तर्योजक ट्रांसफार्मर (Inter-connecting Transformers) (ICTS): प्रत्येक ICT bank (तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक साथ) एक अवयव होगा।

(ग) Static VAR Compensator (SVC): SVC ट्रांसफार्मर के साथ SVC एक अवयव होगा। तथापि 50% आगमनात्मक (inductive) तथा 50% धारित्र (capacitive) रेटिंग हिसाब में ली जाएगी।

(घ) स्विचिड बस रिऐक्टर: प्रत्येक स्विचिड बस रिऐक्टर एक अवयव माना जाएगा।

(3) प्रत्यावर्ती धारा (AC) पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की संगणना निम्नवत की जाएगी:—

प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रणाली हेतु उपलब्धता प्रणाली की प्रतिशतता

$$= \frac{o \times AV_o + p \times AV_p + q \times AV_q + r \times AV_r}{o + p + q + r} \times 100$$

जहां—

o	से	ए0सी0 लाईन्ज की कुल संख्या अभिप्रेत है,
AVo	से	ए0सी0 लाईन्ज की o संख्या की उपलब्धता अभिप्रेत है,
p	से	स्विचिड बस रिऐक्टरज की कुल संख्या अभिप्रेत है,
AVp	से	स्विचिड बस रिऐक्टरज की p संख्या की उपलब्धता अभिप्रेत है,
q	से	ICTs की कुल संख्या अभिप्रेत है,
AVq	से	ICTs की q संख्या की उपलब्धता अभिप्रेत है,
r	से	SVCs की कुल संख्या अभिप्रेत है,
AVr	से	SVCs की r संख्या की उपलब्धता अभिप्रेत है,

(4) पारेषण अवयवों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए भारित कारक, निम्नवत होंगे:—

(क) प्रत्यावर्ती धारा (AC) Line के प्रत्येक परिपथ (circuit) के लिए: प्रतिकर रहित ए0सी0 लाईन्ज की सर्ज इम्पेडेन्स लोडिंग (एस0आई0एल0) Surge Impedance Loading for

uncompensated Line (SIL) को परिपण किलोमीटर से गुणित। विभिन्न वोल्टेज स्त्रों के लिए SIL, रेटिंग तथा कॅन्डकटर कॅन्फिग्यूरेशन का उल्लेख परिशिष्ट I में किया गया है। तथापि परिशिष्ट-I में उल्लिखित न किए गए वोल्टेज स्त्रों तथा/अथवा कॅन्डकटर कॅन्फिग्यूरेशन के लिए तकनीकी तर्क पर आधारित समुचित SIL को, दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को सूचित करने के उपरान्त, उपलब्धता की संगणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

- (ख) प्रत्येक ICT bank के लिए: रेटिड MVA क्षमता।
- (ग) SVC के लिए: रेटिड MVAR (आगमनात्मक तथा धात्रि) क्षमता।
- (घ) स्विचिड बस रिऐक्टर: रेटिड MVAR क्षमता।

(5) पारेषण अवयवों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उपलब्धता की संगणना भारत कारक विचाराधीन कुल घण्टों तथा उस प्रवर्ग के प्रत्येक अवयव के लिए अनुपलब्ध घण्टों पर आधारित होगी। पारेषण अवयवों के प्रत्येक प्रवर्ग की उपलब्धता की संगणना के सूत्र (फार्मूले) परिशिष्ट-II के अनुसार होंगे।

(6) पारेषण अवयव अनुपयोगकाल में, निम्नलिखित कारणों से, जिनके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी न हो, उपलब्ध समझे जाएंगे:—

- (क) अपने पारेषण प्रणाली के रख-रखाव अथवा निर्माण के लिए अन्य एजेंसी/ एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए गए पारेषण अवयवों का बन्द होना;
- (ख) अति वोल्टेज से मैन्यूअल ट्रिपिंग अथवा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों के अनुसार स्विचिड बस रिऐक्टर की मैन्यूअल ट्रिपिंग।

(7) विचाराधीन अवधि में कुल अवयव काल में से निम्नलिखित आपतित घटनाओं में पारेषण अवयव के अनुपयोगकाल को निकाला जाएगा:—

- (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियन्त्रण से बाहर दैवकृत तथा अपरिहार्य घटना के कारण अवयव अनुपयोगकाल;
- (ख) ग्रिड आपातों/विघ्नों के कारण, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी न हो, अनुपयोगकाल, उदाहरणतया ग्रिड विघ्नों से उपकेन्द्र में खराबी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अवयवों में अनुपयोगकाल के कारक अन्य एजेंसी के स्वामित्वाधीन बेज (bays); लाईनों की ट्रिपिंग, ICTs इत्यादि। यदि अवयव को ग्रिड आपाती/विघ्न के पश्चात् प्रणाली को युक्तियुक्त समय में बहाल करते हुए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र/राज्यभार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों के अनुसार न किया जाता है तो पूर्ण अनुपयोगकाल अथवा अनुपयोगकाल, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है, के लिए अवयव उपलब्ध नहीं माना जायेगा।

(8) यदि अवयव अनुपयोगकाल के उत्पादन केन्द्र पर उत्पादन में हानि होती है, तो उस अवयव अनुपयोगकाल के लिए उन दिनों, जिन पर उत्पादन में हानि हुई है, के लिए वास्तविक अनुपयोगकाल का दोगुणा समझा जाएगा।

परिशिष्ट-I
[उपाबन्ध क का पैरा (4)(क) देखें]

प्रत्यावर्ती धारा (AC) लाईन की सर्ज इम्पेडेन्स लोडिंग (SIL)

क्रम संख्या	किलोवाट वोल्टेज (KV)	कन्डक्टर कॉन्फिगरेशन	एस0आई0एल0 (SIL) (मेगावाट) MW
1.	400	क्वेट्र वसीमीस	691
2.	400	टविन मूस	515
3.	400	क्वेट्र ए0ए0ए0सी0	425
4.	400	क्वेट्र जेब्रा	647
5.	400	क्वेट्र ए0ए0ए0सी0	646
6.	400	ट्रिपल स्नोबर्ड	805
7.	400	एसीकेसी (500/26)	558
8.	400	टविन एसीएआर	557
9.	220	टविन जेब्रा	175
10.	220	सिंगल जेब्रा	132
11.	132	सिंगल पैनथर	50
12.	66	सिंगल डॉग	10

परिशिष्ट-II
[उपाबन्ध क का पैरा (5) देखें]

पारेषण अवयव के प्रत्येक प्रवर्ग की उपलब्धता की संगणना के सूत्र

$$AVO \text{ ए0सी0 लाईन्ज की } o \text{ संख्या की उपलब्धता} = \frac{\sum_{l=1}^o \frac{W_l(T_l - T_{NAI})}{T_l}}{\sum_{l=1}^o W_l}$$

$$AVq(ICTs \text{ की } q \text{ संख्या की उपलब्धता}) = \frac{\sum_{k=1}^q \frac{W_k(T_k - T_{NAK})}{T_k}}{\sum_{k=1}^q W_k}$$

$$AVr(SVCs \text{ की } r \text{ संख्या की उपलब्धता}) = \frac{\left[\sum_{l=1}^r \frac{0.5 W_{ll}(T_{ll} - T_{NAI})}{T_{ll}} + \sum_{l=1}^r \frac{0.5 W_{cl}(T_{cl} - T_{NACL})}{T_{cl}} \right]}{\left[\sum_{l=1}^r 0.5 W_{ll} + \sum_{l=1}^r 0.5 W_{cl} \right]}$$

$$AVS \text{ (स्विचड बस रिऐक्टरज की } s \text{ संख्या की उपलब्धता)} = \frac{\sum_{m=1}^s \frac{W_m(T_m - T_{NAM})}{T_m}}{\sum_{m=1}^s W_m}$$

जहां

W_i = i^{th} पारेषण लाईन का भारित कारक

W_k = k^{th} ICT का भारित कारक

W_{il} & W_{cl} = l^{th} SVC के आगमनात्मक तथा धारित्र प्रचालन का भारित कारक

W_m = m^{th} बस रिऐक्टर का भारित कारक

T_i, T_k, T_{il}, T_{cl} , & T_m = i^{th} ए0सी0 लाईन, K^{th} आई0सी0टी0, l^{th} एस0वी0सी0 (आगमनात्मक प्रचालन), l^{th} एस0वी0सी0 (धारित्र प्रचालन) तथा m^{th} स्विचड बस रिऐक्टर बलॉक के विचाराधीन अवधि के दौरान पूर्ण घण्टे (उपाबन्ध- “क” में अधिकथित प्रक्रिया के पैरा 7 में दिये कारणों पर उस अनुपयोगकाल, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, को निकालते हुए) ।

T_{nai} , T_{nak} - T_{nai} , & T_{naci} , T_{nam} = i^{th} ए0सी0 लाईन K^{th} आई0सी0टी0, l^{th} एस0वी0सी0 (आगमनात्मक प्रचालन - Inductive operation) l^{th} एस0वी0सी0 (धारित्र प्रचालन - Captive Operation) तथा स्विचड बस रिऐक्टर ब्लाक के अनुपलब्ध घण्टे (उपाबन्ध - “क” में दी गई प्रक्रिया के पैरा 6 के अनुसार, अनुपयोगकाल, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, समझी गई उपलब्धता को निकालते हुए) ।

उपाबन्ध-ख
[विनियम 27 के मद-विनियम (2) देखें]

राज्य ग्रिड से संयोजन के लिए पंजीयन हेतु आवेदन

क्रम
संख्या

1. उत्पादन कम्पनी/ अनुज्ञप्तिधारी का नाम
2. पंजीकृत पता
3. दूरभाष नम्बर/फैक्स नम्बर/ई-मेल आई. डी.
4. उत्पादन क्षमता.- उत्पादन केन्द्र की दशा में उसकी अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)
5. पारेषण क्षमता.- पारेषण नेटवर्क की दशा में उसमें संचालित (हैनडल्ड) ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट्स में) ।
6. राज्य ग्रिड से संयोजन की प्रस्तावित तारीख
7. अन्तर्योजन बिन्दु का विवरण (यदि आवश्यक हो, पृथक से कागज लगाएं)
8. राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय पंजीयन शुल्क के मांगदेय ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख

9. वचनबद्ध

हम एतद्वारा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रिड प्रबन्धन हेतु जारी अनुदेशों का पालन करने का वचन देते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

टिप्पणी.—राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन कम्पनियों तथा पारेषण कम्पनियों सके प्राप्त करने वाला आवश्यक तकनीकी विवरण पृथक से विहित कर सकेगा व प्राप्त कर सकेगा।

उपाबन्ध-ग
विनियम (29) देखें

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वार्षिक राजस्व अपेक्षा एवं राजस्व दायरीकरण हेतु आरूप

आरूप सारांश :

1.	पत्र	एस-1	लाभ हानि खाता
2.	पत्र	एस-2	तुलन पत्र
3.	पत्र	एस-3	रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र
4.	पत्र	एस-4	वार्षिक राजस्व अपेक्षा

वित्तीय आरूप :

5.	पत्र	एफ-1	प्रभारों से राजस्व
6.	पत्र	एफ-2	परियोजना-वार/ योजना वार पूंजीगत व्यय
7.	पत्र	एफ-3	उपयोग में न आ रही सम्पत्तियों का विवरण
8.	पत्र	एफ-4	घरेलू ऋण, बाण्ड्स तथा वित्तीय सौकार्य
9.	पत्र	एफ-5	मुरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय
10.	पत्र	एफ-6	कर्मचारी लागत एवं प्रावधान
11.	पत्र	एफ-7	प्रशासन एवं सामान्य व्यय
12.	पत्र	एफ-8	स्थाई परिसम्पत्तियां तथा अवक्षयण हेतु प्रावधान
13.	पत्र	एफ-9	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार
14.	पत्र	एफ-10	पूँजीकृत व्यय विवरण
15.	पत्र	एफ-11	उधार खाते (डेबिट), बटटे खाते (अपलेखन) तथा कोई अन्य मद
16.	पत्र	एफ-12	विविध देनदारों तथा डूबत व संदिग्ध देनदारियों के लिए प्रावधान का विवरण
17.	पत्र	एफ-13	असाधारण मद
18.	पत्र	एफ-14	पूर्वावधि शुद्ध व्यय/आय

प्रभार सूची :

19.	पत्र	प्रभार सूची	विद्यमान व प्रस्तावित प्रभार सूची
-----	------	-------------	-----------------------------------

उपयोगिताओं हेतु अनुदेश :

- सीडी/फ्लोपी के रूप में इलेक्ट्रानिक प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाएगी।
- ये आरूप संकेतक प्रकृति के हैं तथा लाईन मदों को उपयोगिता अपने लेखा सारणी के अनुसार मदों को समरेखित सम्बद्ध कर सकती है।
पि. व. — पिछला वर्ष
चा. व. — चालू वर्ष
आ. व. — आगामी वर्ष

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एस-1

सभी आंकड़े करोड़ रु० में

लाभ हानि खाता

	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
क	राजस्व			
1.	प्रभारों से राजस्व			
2.	अन्य आय			
	कुल राजस्व या आय			
ख	व्यय			
1.	मरम्मत एवं अनुरक्षण			
2.	कर्मचारी लागत			
3.	प्रशासन एवं सामान्य व्यय			
4.	पूर्वावधि शुद्ध जमा (क्रेडिट) प्रभार			
5.	अन्य उधार खाते-बट्टे खाते			
6.	असाधारण मर्दे			
7.	घटाएँ- पूँजीकृत व्यय			
ग	ब्याज तथा करों से अवक्षयण से पूर्व लाभ			
घ	अवक्षयण तथा सम्बद्ध उधार खाते			
ङ	ब्याज तथा करों से पूर्व लाभ			
1.	ब्याज एवं वित्त पोषण प्रभार			
2.	घटायें : पूँजीकृत ब्याज			
च	कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार			
छ	कुल व्यय			
ज	कर से पूर्व लाभ/हानि			
झ	आय-कर			
ञ	कर के पश्चात् लाभ/हानि			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एस-2

सभी आंकड़े करोड़ रु० में

तुलन पत्र

	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
	निधियों के स्रोत			
क	अंशधारियों की निधि			
	(क) अंश पूँजी			
	(ख) आरक्षित व अधिशेष			
ख	परियोजना लागत के प्रति विशेष विनियोग			
ग	ऋण निधियां			
	(क) सुरक्षित ऋण			
	(ख) असुरक्षित ऋण			

(घ)	निधियों के अन्य स्त्रोत			
१	स्त्रोत योग			
II	निधियों की प्रयोज्यता			
क	स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
	(क) सकल खण्ड			
	(ख) घटायें :- संचित अवक्षयण			
	(ग) शुद्ध खण्ड			
	(घ) पूँजीगत प्रगत्याधीन संकर्म			
	(ङ) घटायें :- तब तक अप- लिखित राशि			
ख	निवेश			
ग	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम			
	(i) चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(ii) ऋण एवं अग्रिम			
घ	घटायें :- चालू देयतायें एवं प्रावधान			
	(i) चालू देयतायें			
	(ii) प्रावधान			
ङ	शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ			
च	बही खाते तथा न डाली गई सीमा तक विविध व्यय			
	प्रयोज्यता निधियों का योग			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं एस-3
सभी आंकड़े करोड़ रु० में

रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र

	विशिष्टियाँ	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
I.	प्रचालनों से शुद्ध निधियाँ			
1.क	उपार्जनों से शुद्ध निधियाँ			
	कर से पूर्व लाभ			
	घटायें :- वर्ष के दौरान आयकर भुगतान			
	क का योग			
ख	जोड़ें :- रोकड़ बहिर्वाह आवश्यकता न होने वाले राजस्व खाते को जमा			
	(i) अवक्षयण			
	(ii) स्थगित लागत का क्रमिक उपाकरण			
	(iii) अमूर्त परिसम्पत्तियों का क्रमिक का उपाकरण			

	(iv) निवेश मत्ता आरक्षित (v) अन्तः यदि कोई है ख का योग		
1	घटाना में सभ्यता के खाते को जमा, जिनमें शेकड़ प्राप्त अन्तर्निष्ठ नहीं है (i) अवकाश (ii) ----- ग का योग		
2	उपार्जन से शुद्ध निधियां (क+ख+ग)		
3	स्थाई परिसंपत्तियों के नियन्त्रण से प्राप्तियां		
4	प्रचालनों से कुल निधियां		
	कामकाजी पूंजी में शुद्ध वृद्धि / कमी क साल परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी (क) सामग्री सूची (ख) प्राप्तिगत (ग) सभा व अतिथि क का योग		
	ख साल वेगताओं में वृद्धि / कमी (क) कामकाजी पूंजी के लिए उधार (ख) अन्य ख का योग		
	कामकाजी पूंजी में शुद्ध वृद्धि / कमी (क ख) योग I (प्रचालनों से शुद्ध निधियां) पूंजीगत वेगताओं में शुद्ध वृद्धि / कमी क नवीन उधार / सभा (क) राज्य सभा (ख) निवेश मुदा सभा उधार (क्रेडिट) (ग) अन्य उधार / सभा क का योग		
	ख नामगो अदायगियां मूलधन की नामगो अदायगी (क) राज्य सभा (ख) निवेश मुदा सभा / उधार (क्रेडिट) (ग) अन्य उधार / सभा ख का योग		
	योग II पूंजीगत वेगताओं में शुद्ध वृद्धि / कमी (क-ख) सामग्री पूंजी में वृद्धि / कमी योग III पूंजीगत व्ययों के लिए उपलब्ध कुल निधियां (I+II+III)		
III			
IV			

V	पूँजीगत व्यय पर मन योग में ली गई तिथियां		
	(क) परिमोचनाओं पर		
	(ख) विमुक्त परिमोचनियों संकलों को पुनर्निर्माणित		
	(ग) अपूर्ण परिमोचनियों		
	(घ) आरम्भित लागत		
	र का योग		
VI	निवेशों में शुद्ध वृद्धि / कमी		
VII	रोकड़ न बैंक अतिशेषों में शुद्ध वृद्धि / कमी (IV V VI)		
VIII	जोड़ें आरम्भिक रोकड़ एवं बैंक शेष		
IX	अन्तिम रोकड़ एवं बैंक अतिशेष (VII+VIII)		

राज्य भार प्रेषण कर्त

आरम्भ सं० पृ० ५
सभी अधिक कसेड को न

वार्षिक सभसत अगसा

	तिथिदिनां	विधला वर्ष वारतनिक	सालू वर्ष अनुमानित	आगामी वर्ष प्रक्षेपण
1.	प्राप्तिगां (क) तिथि प्रगाशों से सभसत (ख) अन्य आय योग			
2.	व्यय (क) पुरगत एवं अनुसक्षण (ख) कमीनाशी व्यय (ग) प्रशासनिक एवं सागान्य (घ) अन्तर्गत (ङ) व्याज तथा निस्त मोषण प्रसार (च) धनगतः पूँजीकृत व्याज न अन्य व्यय (छ) अन्य डेबिट (खुबत सभ सेतु धानधान भवित) (ज) आराधारण मन (झ) अन्य (तिथि) - पूँजीगत शुद्ध क्रेडिट योग			
3.	वार्षिक सभसत अगसा			
4.	प्रसार संशोधन से पूँजी अतिशेष (I) / कमी ()			
5.	प्रसार संशोधन का रंधित			
6.	प्रसार संशोधन के भुक्तात् अतिशेष (I) कमी (-)			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-1

प्रभारों से राजस्व

	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		राजस्व	राजस्व	राजस्व
		करोड़ रु० में	करोड़ रु० में	करोड़ रु० में
1.	अनुज्ञापिधारी			
2.				
3.				
4.	उत्पादक			
5.				
6.				

टिप्पणी.—यह आरूप विद्यमान प्रभारों की सूची के अनुसार भरा जाना चाहिए।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-2

परियोजना/ योजनावार पूंजीगत व्यय
(नई परियोजनाएं तथा प्रगत्याधीन पूंजीगत संकर्म)

क्र. सं.	विशिष्टियां	परियोजना लागत		लागत संशोधन के कारण	प्रक्षेपित संकर्म योजना		विलम्ब के कारण	विगत वर्ष के अन्त तक व्यय	वर्ष के दौरान व्यय	निर्माण के दौरान व्यय	कटौतियां/स्था-नान्तरण	स्थाई परि-सम्पत्तियों का अन्तरण	पूँजी के स्त्रोत
		मूल अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल समापन तारीख	संशोधित समापन तारीख						(व्याज + पूंजीकृत व्यय)	संस्थापार उप-लब्ध राशि
	द्वितीय वर्ष •												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

●टिप्पणी.—सूचना पिछले वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिए दी जानी है।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-3
सभी आंकड़े करोड़ रु. में

उपयोग में न आ रही सम्पत्तियों का विवरण पत्र

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष * अवाप्ति/संस्थापन की तारीख	ऐतिहासिक लागत/ अवाप्ति लागत	प्रचालनों के प्रत्याहरण की तारीख	प्रत्याहरण की तारीख को संचायी अवक्षयण	प्रत्याहरण की तारीख को घटा हुआ मूल्य

* टिप्पणी.—सूचना पिछले वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिए दी जानी है।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-4
सभी आंकड़े करोड़ रु. में

घरेलू ऋण, बाण्ड्स तथा वित्तीय सौकार्य

क्र. सं.	विवरितियां	वर्ष के प्रारम्भ अतिशेष				वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि	मूलधन की वापसी अदायगी		ब्याज			अन्तिम शेष
	करोड़ रु. में	अत्यधिक न हुआ मूलधन	अत्यधिक मूलधन	अत्यधिक मूलधन पर ब्याज—	योग		देय	संदत्त	देय	संदत्त	प्रति-शत	
	वित्तीय वर्ष*											
क	दीर्घ-कालीन											
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम											
2.	ग्रामीण विद्युत्तिकाकरण निगम											
3.	ऊर्जा वित्त निगम											
4.	बाण्ड्स											
5.	बैंक											
6.	त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम											
7.	अन्य कोई											
8.												
ख	लघुकालीन											
	योग											

* टिप्पणी.—सूचना पिछले वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिए दी जानी है।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-5
सभी आंकड़े करोड़ रुपये में

मुरम्मत एवं अनुस्क्षण व्यय

	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
योग				

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-6

कर्मचारी लागत तथा प्रावधान

	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		अनन्तिम	अनुमानित	प्रक्षेपण
क	कर्मचारी बल			
	वर्ष के प्रारम्भ में कार्यरत बल			
	कर्मचारी प्रवर्ग			
1.				
2.				
3.				
4.				
योग				
	वर्ष के प्रारम्भ में स्वीकृत बल			
	कर्मचारी प्रवर्ग			
1.				
2.				
3.				
4.				
योग				

ख	कर्मचारी लागत			
1.	वेतन			
2.	महंगाई भत्ता			
3.	अन्य भत्ते व अनुतोष			
4.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			
5.	अवकाश यात्रा अभिदाय			
6.	शुल्क एवं मानदेय			
7.	प्रोत्साहन/पुरस्कार (सांझेदारी परियोजना वाले सहित) मदों का उल्लेख करें			
8.	अर्जित अवकाश नकदीकरण			
9.	शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति			
10.	अवकाश वेतन अंशदान			
11.	कर्मकार प्रतिकर तथा उपादान के अन्तर्गत भुगतान			
12.	कर्मचारियों को साहाय्य प्राप्त विद्युत			
13.	कर्मचारी कल्याणकारी व्यय			
ग	प्रशिक्षु तथा अन्य प्रशिक्षण व्यय			
घ	भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन तथा उपदान को भुगतान/अंशदान			
	1. सेवान्त प्रसुविधायं			
	(क) अभीदायी निधि अंशदान			
	(ख) भविष्य निधि अंशान			
	—निवेशित			
	—अनिवेशित			
	(ग) पेंशन भुगतान			
	(घ) उपदान भुगतान			
	(ङ) अवकाश नकदीकरण भुगतान			
	2. अन्य कोई मद			
	योग — घ			
ङ	कर्मचारियों को बोनस/ अनुग्रह			
च	कुल योग			
छ	निर्माण संकर्मों को प्रभार्य			
	(च) का शेष मद (च-छ)			
	मजदूरी वृद्धि का सुसंगत सूचकांक (वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में)			
	थोक मूल्य सूचांक			
	उपभोक्ता मूल्य सूचांक			
	महंगाई भत्ता दर			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं0 एफ-7

प्रशासन एवं सामान्य व्यय

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		अनन्तिम	अनुमानित	प्रक्षेपण
	करोड़ रु. में			
क	प्रशासन व्यय			
1.	किराया रेटस् तथा कर (आय व लाभ पर सभी करों के अलावा)			
2.	कर्मचारियों परिसम्पत्तियों, विधिक दायित्व का बीमा			
3.	दूरभाष, डाक, तार, इन्टरनेट प्रभार			
4.	कर्मचारियों / बाहर वालों को प्रोत्साहन/पुरस्कार परामर्श शुल्क			
5.	परामर्श प्रभार			
6.	तकनीकी शुल्क			
7.	अन्य व्यावसायिक प्रभार			
8.	वाहन तथा यात्रा (वाहन किराया, प्रचालन)			
9.	बाह्य अभिकरणों को संदत्त सुरक्षा/सेवा प्रभार			
10.	विनियामक व्यय			
	मद प्रशासकीय व्ययों का योग			

ख	अन्य प्रभार			
1.	शुल्क तथा पत्र-पत्रिकाओं हेतु अभिदान			
2.	मुद्रण व लेखन सामग्री			
3.	विज्ञापन (क्रय से सम्बन्धित को छोड़ कर) प्रदर्शन व निरूपण व्यय			
4.	बाह्य संस्थाओं/संघों को अंशदान/चन्दा			
5.	कार्यालयों को विद्युत प्रभार			
6.	जल प्रभार			
7.	कोई अध्ययन			
8.	विविध व्यय			
9.	अन्य कोई प्रभार			
10.	विधिक प्रभार			
11.	अंकेक्षक शुल्क			
12.	भाड़ा- सामग्री सम्बन्धित व्यय			
	कुल प्रभार			
	पूँजीगत संकर्मों को प्रभार्य कुल प्रभार			
	राजस्व व्ययों को प्रभार्य कुल प्रभार			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-8

स्थाई परिसम्पत्तियां तथा अवक्षयण हेतु प्राक्धान

क्र. सं.	विशिष्टता	पिछला वर्ष										
		सकल स्थाई परिसम्पत्तियां				अवक्षयण हेतु प्राक्धान				शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां		
		वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन कटीती	वर्ष के अन्त में	अव-क्षयण की दर	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन व कटीती	वर्ष के अन्त में	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के अन्त में
1.	भूमि एवं भू-अधिकार											
2.	मकान व सिविल संकर्म											
	अन्य-1											
	अन्य-2											
	अन्य-3											
	मद-योग											
3.	संचार उपकरण											
4.	वाहन											
5.	फर्नीचर व फिक्स्चर											
6.	कार्यालय उपकरण											
7.	ली गई परिसम्पत्तियां तथा अन्तिम मूल्यांकन लम्बित											
8.	अन्य कोई मद											
	योग (1 से 8)											

टिप्पणी-1 यदि निर्धारण किया गया हो तो परिसम्पत्तियों का युक्ति-युक्त मूल्य दें।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-8
सभी आंकड़े करोड़ रु. में

स्थाई परिसम्पत्तियां तथा अवक्षयण हेतु प्रावधान—(जारी है)

क्र. सं.	विशिष्टियां	चातु वर्ष										
		सकल स्थाई परिसम्पत्तियां				अवक्षयण हेतु प्रावधान				शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां		
		वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन कटीती	वर्ष के अन्त में	अव-क्षयण की दर	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन व कटीती	वर्ष के अन्त में	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के अन्त में
1.	भूमि एवं भू-अधिकार											
2.	भवन व सिविल संकर्म											
	अन्य-1											
	अन्य-2											
	अन्य-3											
	मद-योग											
3.	संचार उपकरण											
4.	वाहन											
5.	फर्नीचर व फिकस्चर											
6.	कार्यालय उपकरण											
7.	ली गई परिसम्पत्तियां तथा अन्तिम मूल्यांकन लम्बित											
8.	अन्य कोई मद											
	योग (1 से 8)											

टिप्पणी-1. यदि निर्धारण किया गया हो तो परिसम्पत्तियों का युक्ति-युक्त मूल्य उपलब्ध करवायें।

आरूप सं० एफ-8
समी आंकड़े करोड़ रु. में

स्थाई परिसम्पत्तियां तथा अवक्षयण हेतु प्रावधान—(जारी है)

क्र. सं.	विशिष्टता	आगामी वर्ष										
		सकल स्थाई परिसम्पत्तियां				अवक्षायण हेतु प्रावधान					शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां	
		वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन कटौती	वर्ष के अन्त में	अव-क्षायण की दर	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान परि-वर्धन	समा-योजन व कटौती	वर्ष के अन्त में	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के अन्त में
1.	भूमि एवं भू-अधिकार											
2.	भवन व सिविल संकर्म											
	अन्य-1											
	अन्य-2											
	अन्य-3											
	मद-योग											
3.	संचार उपकरण											
4.	वाहन											
5.	फर्नीचर व फिकरर											
6.	कार्यालय उपकरण											
7.	ती गई परिसम्पत्तियां तथा अन्तिम मूल्यांकन लम्बित											
8.	अन्य कोई मद											
	योग (1 से 8)											

टिप्पणी-1. यदि निर्धारण किया गया हो तो परिसम्पत्तियों का युक्ति-युक्त मूल्य दें।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-9

ब्याज एवं वित्त प्रभार

क्र.	विवरण	विवरण	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
			वास्तविक	प्रक्षेपित	प्रक्षेपित
		करोड़ रु. में			
क	I.	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/संगठनों से दीर्घकालीन ऋण/उधारों पर ब्याज व वित्त प्रभार			
		1. भारतीय जीवन बीमा निगम			
		2. ग्रामीण विद्युतिकरण निगम			
		3. पावर वित्त निगम			
		4. बाण्डस्			
		5. बैंक/वित्तीय संस्थान			
		6. त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम			
		7. अन्य कोई			
		I का योग			
	II.	कार्यशील पूंजी ऋणों या अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज			
		क का योग : I + II			
ख		अन्य ब्याज एवं वित्त प्रभार			
		1. वित्त उस्थित करने के व्यय एवं बैंक प्रभार आदि			
		2. दायित्वक ऋण प्रभार			
		3. पट्टा किराया			
		4. ऊर्जा क्रय के भुगतान में विलम्ब के लिए शास्ति प्रभार			
		ख का योग			

ग			व्याज एवं वित्त प्रभार का कुल योग : (क+ख)			
१६			घटायें : पूजी खाते को प्रभार्य व्याज व वित्त प्रभार			
३			राजस्व खाते हेतु: ध्यान व वित्त प्रभारों का कुल योग (ग-घ)			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं. एफ-10
सभी आंकड़े करोड़ रु० में

पूजीकृत व्यय विवरण

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष वास्तविक	चालू वर्ष अनुमानित	आगामी वर्ष प्रक्षेपण
1.	पूजीकृत व्याज एवं वित्त प्रभार			
2.	पूजीकृत अन्य व्यय :			
	(क) कर्मचारी व्यय			
	(ख) मुरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय			
	(ग) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय			
	(घ) अन्य, यदि कोई है			
	2 का योग			
	कुल योग			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं. एफ-11
सभी आंकड़े करोड़ रु० में

उधार खाते (डेबिट), बट्टे खाते (अपलेखन) तथा कोई अन्य मद

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष वास्तविक	चालू वर्ष अनुमानित	आगामी वर्ष प्रक्षेपण
1.	सामग्री लागत असंगति			
2.	विविध हानियां तथा बट्टे खाते (अपलेखन)			
3.	प्रावैधिक अपलिखित/डूबत ऋण			
4.	पूर्वावधि के शुद्ध क्रेडिट/प्रभार			
	मद-योग			
5.	घटायें : पूंजीगत व्ययों को प्रभार्य			
	राजस्व को प्रभार्य शुद्ध			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

विविध देनदारों तथा डूबत व सन्देहास्पद देनदारियों का विवरण

आरूप सं. एफ-12
सभी आंकड़े करोड़ रु० में

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
1.	वर्ष के प्रारम्भ में ग्राहकों से प्राप्यतायें			
2.	वर्ष के लिए विपत्रित राजस्व			
3.	वर्ष के लिए संग्रहण			
	चालू देयताओं के प्रति			
	पिछले वर्ष तक के बकायों के प्रति			
4.	वर्ष के अन्त में ग्राहकों से सकल प्राप्यताएं			
5.	प्राप्यतायें			
6.	प्रावधान का प्रतिशत			
7.	डूबत तथा सन्देहास्पद देनदारियों के लिए प्रावधान			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-13

असाधारण मद

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
1.	असाधारण क्रेडिट (प्राकृतिक आपदा के कारण हानियों के प्रति सहायिकियों सहित)			
	कुल क्रेडिट			
2.	असाधारण डेबिट (प्राकृतिक आपदा के कारण हानियों के प्रति सहायिकियों सहित)			
	कुल डेबिट			
	कुल योग			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप सं० एफ-14

पूर्वावधि शुद्ध व्यय/आय

क्र. सं.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		वास्तविक	अनुमानित	प्रक्षेपण
क	पिछले वर्षों से सम्बन्धित आय			
1.	पूर्वावधियों के लिए ब्याज आय			
2.	पूर्वावधि आय कर			
3.	अवक्षयण के लिए अधिक प्रावधान			
4.	ब्याज व वित्त प्रभार के लिए अधिक प्रावधान			
5.	उपभोक्तों से प्राप्तियां			
6.	अन्य अधिक प्रावधान			
7.	अन्य आय			
	मद-योग 'क'			
ख	पिछले वर्षों से सम्बन्धित व्यय			
1.	प्रचालन व्यय			
2.	कर्मचारी लागत			
3.	अवक्षयण			
4.	ब्याज तथा वित्त प्रभार			
5.	प्रशासनिक व्यय			
6.	राजस्व प्रभारों का प्रत्याहरण			
7.	सामग्री सम्बन्धित			
8.	अन्य			
	मद-योग 'ख'			
	पूर्वावधि शुद्ध क्रेडिट (प्रभार) (क-ख)			

राज्य भार प्रेषण केन्द्र

आरूप प्रभार सूची

विद्यमान तथा प्रस्तावित प्रभार सूची

क्र. सं.	प्रयोक्ता वर्ग	विद्यमान प्रभार		प्रस्तावित प्रभार	
		प्रति संयोजन मासिक नियत प्रभार (रु०)	कुल राजस्व	प्रति संयोजन मासिक नियत प्रभार (रु०)	कुल राजस्व
1.	अनुज्ञापिधारी				
2.					
3.					
4.	उत्पादक				
5.					
6.					
7.					

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION***Shimla, the 14th September, 2006*

No. HPERC/421.—In exercise of the powers conferred under clauses (g), (h), (i), (zd) and (zf) of sub-section (2) of section 181 read with sub-section (3) of section 32, section 36, clause (d) of sub-section (2) of section 39, sub-clause (i) of clause (c) of section 40 and sections 61 and 62 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS**PART-I****PRELIMINARY**

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Charges for Transmission, Wheeling and Intervening Facilities and Fees and Charges to be collected by the State Load Despatch Centre) Regulations, 2006.

(2) The regulations contained in Part-II shall be applicable to persons engaged in the business of transmission or wheeling of electricity, in the State of Himachal Pradesh, and the regulations contained in Part-III, shall apply to the licencees engaged in intra-State transmission of electricity and generating companies that are connected to the State Grid and monitored/ serviced by the State Load Despatch Centre in the State of Himachal Pradesh. The phrase “licensee engaged in intra-State transmission of electricity” includes all transmission, distribution and trading licencees.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “access agreement” means an agreement entered into between a transmission licensee and an applicant to avail open access to the licensee’s network for transmission of electricity;
- (c) “availability” in relation to a transmission system for a given period means the time in hours during that period the transmission system is capable to transmit electricity at its rated voltage and shall be expressed in percentage of total hours in the given period;
- (d) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

- (e) "Conduct of Business Regulations" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005;
- (f) "Grid Code" means the Grid Code specified by the Central Commission under clause (h) of sub-section (1) of section 79 of the Act and includes the State Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of section 86 of the Act or deemed approved under clause (b) of section 172 of the Act ;
- (g) "licence" means a licence granted under section 14 of the Act and shall include the deemed licence;
- (h) "licensee" means a person who is granted a licence or is a deemed licensee under section 14 of the Act;
- (i) "long-term transmission customer" means a person availing or intending to avail access to the intra-State transmission system for a period of five years or more;
- (j) "other business" means any business of the transmission or distribution licensee other than the licensed business;
- (k) "short-term transmission customer" means a transmission customer other than the long-term transmission customer; and
- (l) "State" means the State of Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings as are assigned to them in the Act.

PART-II

TRANSMISSION, WHEELING AND INTERVENING FACILITIES CHARGES

3. *Tariff determination by bidding process.*—Notwithstanding anything specified in these regulations, the Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

4. *Periodicity for determination of transmission/wheeling charges.*—(1) Unless the Commission adopts multi year tariff principles in accordance with the tariff guidelines and the regulations framed by the Commission, the charges for a licensee shall be determined every year and shall not be ordinarily amended more than once in a year.

(2) Subject to other provisions of these regulations, the charges allowed, revenue permitted and expenses assessed for any financial year, shall be subject to adjustments in any charges to be fixed for the subsequent period, if the Commission is satisfied, that such adjustments for the excess amount or shortfall in the amount actually realized or expenses incurred are necessary and justified.

5. *Petition for determination of transmission/wheeling charges.*—(1) Every Licensee shall on or before the 30th November, submit a petition to the Commission for determination of transmission charges or wheeling charges on an annual basis, or as frequently as desired by the Commission, duly following the procedure as laid down in the Conduct of Business Regulations.

(2) The petition by a licensee for determination of charges shall be accompanied by information in formats specified by the Commission in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005 as amended from time to time. The information for the previous period(s) should be based on audited accounts and for the periods for which audited accounts are not available, un-audited accounts should be filed:

Provided that, in the absence of information filed by the licensee, the Commission, if it so desires, may initiate *suomotu* proceedings for determination of charges.

The petition for determination of transmission charges or wheeling charges shall contain detailed justification for incurrence or proposed incurrence of each cost item forming part of the Annual Revenue Requirement.

6. *Orders by the Commission.*—(1) The Commission may require the licensee to furnish any further information, particulars, documents, public records etc. as the Commission may consider appropriate to enable it to assess the petition.

(2) The Commission shall analyse the petition submitted by the licensee and assess the prudence of the costs and revenue items incurred or proposed to be incurred duly taking into account the petitioner's justifications, the objections to the petition and information from other sources, if sought by the Commission.

(3) The Commission, after completing all proceedings related to tariff determination in accordance with the Conduct of Business Regulations, shall issue an Order on transmission charges or wheeling charges within 120 days of the acceptance of the petition filed by the licensee.

7. *Publication of transmission/wheeling charges.*—The licensee shall within the time given in the order of the Commission, publish the salient features of the charges, in two daily newspapers, one each in Hindi and English language, having wide circulation in its licensed area. The charges so determined by the Commission shall come into force from the applicable date as given in the Commission's Order and shall cease to operate, unless allowed to be continued for a further period with such variations or modifications, as may be ordered by the Commission.

8. *Communication of Order.*—The Commission shall, within seven days of making the Order, send a copy of the Order to the Government of Himachal Pradesh, the Central Electricity Authority, concerned licensees and generating companies. The Commission shall also make available, copy of the said order to any person on payment of a fee as specified under sub-regulation (9) of regulation 24 of the Conduct of Business Regulations.

9. *Refund of excess amount.*—The licensee shall recover the charges as determined by the Commission. If any licensee recovers charges exceeding those determined by the Commission, the excess amount shall be refunded to the person who has paid such excess charges, alongwith interest

equal to the prevalent short term Prime Lending Rate of the State Bank of India without prejudice to any other liability incurred by such licensee.

10. Target availability for recovery of full transmission charges.—The target availability for recovery of full transmission charges shall be:

- (1) the Alternating Current (AC) System : 98% .
- (2) the High Voltage Direct Current (HVDC) bi-pole links and the High Voltage Direct Current (HVDC) back-to-back stations : 95%

Note-1.—Recovery of fixed charges below the level of target availability shall be on pro rata basis. At zero availability, no transmission charges shall be payable.

Note-2.—The target availability shall be calculated in accordance with the procedure laid down in Annexure-“A”.

11. Gross Annual Revenue Requirements.—(1) The charges for transmission or wheeling of electricity shall comprise of the recovery of annual transmission or wheeling charges consisting of the following items:—

- (a) operation and maintenance expenses;
- (b) interest and financing cost on loan capital;
- (c) depreciation;
- (d) return on equity; and
- (e) interest on working capital:

Provided that, till such time that the State Load Despatch Centre (SLDC) is a part of the State Transmission Utility (STU), the State Transmission Utility (STU) shall submit the information on the cost items separately for the State Transmission Utility Business and the State Load Despatch Centre (SLDC) business.

12. Operation and maintenance cost.—(1) Operation and maintenance costs shall comprise of the following:—

- (a) salaries, wages and other employee expenses;
- (b) repair and maintenance;
- (c) administrative and general costs; and
- (d) other miscellaneous expenses, e.g. legal charges, audit fees, lease charges, rents, rates and taxes, etc.

(2) In its petition for determination of charges, the licensee shall submit details of operation and maintenance cost incurred in the previous year and that in the current year, together with the proposals for the ensuing year in complete detail and with appropriate justification, for the approval of the Commission:

Provided that, in order to support its system improvement initiatives, or to rectify any specific shortcomings, etc., the licensee can propose for inclusion of an additional amount over the approved value of operation and maintenance costs during the year. This proposal will be supported by a detailed justification of the specific requirement and any such proposal shall not be admitted by the Commission more than once in any year.

(3) The Commission will finalise, in consultation with the licensee(s), a mechanism to assess the condition of assets on a regular basis, to safeguard against any deliberate under-spending in maintenance and upkeep of the network. To facilitate this, the licensee must finalise preparation of asset register.

13. Asset Base.—(1) The Commission shall determine the Asset Base at the beginning of a financial year, which shall be—

Sum of :

- (A) The Asset Base approved in the previous Order, adjusted for —
 - (i) Actual completed cost of schemes being lower than that approved in such Order;
 - (ii) Cost of schemes or part thereof not completed;
 - (iii) Schemes undertaken on account of certain uncontrollable factors such as changes in law or policies, to meet any emergency, etc, supported by adequate justification.
- (B) Proposed investment plan, to the extent expected to be capitalised during the year, covering (a) schemes for which Commission's approval has been granted, (b) schemes which have been submitted for Commission's approval, and (c) schemes not requiring Commission's approval.

Less :

- (C) Assets proposed to be retired during the year.

(2) The interest on loan capital and return on equity shall be computed on the financing of the cost of schemes included in the asset base as computed under sub-regulation (1).

14. Interest on loan capital.—(1) Interest on loan capital shall be computed loan-wise on the loans approved for the Asset Base. For each loan, the loan outstanding at the beginning of a financial year shall be worked out as gross loan minus cumulative repayments :

Provided that any deviations from the financing arrangements, including the interest rates, the moratorium period, the term of loan, schedule of repayment, etc., shall not be considered if it results in an increase in charges to be paid by the users:

Provided further that the interest cost shall be linked to the Prime Lending Rate of a Scheduled Bank plus pre-determined margin which realistically reflects the rate at which a licensee can raise a debt from the market.

(2) The licensee shall make every effort to reduce its interest cost by financial management such as swapping of loans leading to lower interest costs, or any other financial restructuring, etc. and any benefit on account of these shall be shared in the ratio of 1/3rd with the users, 1/3rd with the licensee and 1/3rd in the Contingency Reserve. The licensee shall submit the calculation of such benefit to the Commission for its approval.

(3) In respect of foreign currency loans, variation in rupee liability due to foreign exchange rate variation, towards interest payment and loan repayment actually incurred, in the relevant year shall be admissible; provided it directly arises out of such foreign exchange rate variation and is not attributable to the licensee or its suppliers or contractors.

15. *Depreciation*.—(1) Depreciation shall be computed in the following manner:—

- (a) depreciation shall be calculated on the original cost of the fixed assets as at the start of a Financial Year;
- (b) the licensee shall, each year provide for depreciation, such sums calculated in accordance with the rates fixed from time to time by the Central Commission, by notification, in the Official Gazette;
- (c) depreciation shall be charged from the first year of operation of the asset. In case, the operation of the asset is for the part of the year, depreciation shall be charged on a pro rata basis.

(2) The depreciation rates fixed by the Central Commission, as referred to in sub-regulation (1), shall also be applicable for distribution with appropriate modifications as may be evolved by the Forum of Regulators.

16. *Return on equity*.—(1) Return on equity shall be computed on the paid up equity capital and shall be post tax, as notified by the Central Commission from time to time, for the transmission licensee.

(2) For distribution, Commission may adopt the rate of return on equity as notified by the Central Commission for the transmission with suitable modifications.

(3) The premium raised by the licensee while issuing share capital and investment of internal resources created out of free reserves, if any, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting capital expenditure in the Asset Base.

(4) Equity invested in foreign currency shall be allowed a return upto the prescribed limit in the same currency and the payment on this account shall be made in Indian rupees based on the exchange rate prevailing on the due date of billing.

17. *Interest on working capital loans*.—(1) Working capital shall include.—

- (a) operation and maintenance expenses for one month;

- (b) maintenance spares @ 1% of the historical cost escalated @ 6% per annum from the date of commercial operation; and
- (c) receivables equivalent to two months of transmission charges calculated on target availability level or wheeling charges.

(2) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be equal to the short-term Prime Lending Rate of the State Bank of India as applicable at the time of determination of the transmission charges. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the licensee has not taken working capital loan from any outside agency.

18. Debt- Equity ratio.—(1) In case of all projects, debt-equity ratio for determination of transmission charges shall be as provided in the Terms and Conditions of Tariff Regulations framed by the Central Commission.

(2) The debt-equity amount arrived in accordance with sub-regulation (1), shall be used in all calculations for calculating interest on loan, return on equity and Foreign Exchange rate variations.

19. Other Income.—All income derived by the licensee from the following sources shall constitute 'Other Income' of the licensee:—

- (a) interest income from investments not appropriated back to Contingencies Reserve;
- (b) interest income from other investments, fixed and call deposits and bank balances;
- (c) rents;
- (d) share of the licensed business from Other Business, if any;
- (e) any other income incidental to the electricity business.

20. Net Annual Revenue Requirement.—The net annual revenue requirement of the licensee eligible for recovery shall be determined after deducting from the gross annual revenue requirement determined under regulation 11, the Other Income determined in accordance with regulation 19.

21. Wheeling Charges.—The Wheeling charges payable by the user of the distribution system shall be determined in accordance with the following formula:—

$$\text{Wheeling Charges} = \frac{\text{Cost of the Distribution System of 11 KV and above}}{\text{Projected units to be sold and wheeled in the distribution licensee's network in the ensuing tariff period:}}$$

Provided that whenever, it is considered necessary and expedient to incentivise the open access in the State, the Commission may, by order, cap the wheeling charges calculated under this regulation.

22. Transmission charges.—(1) The transmission charges payable by a long-term transmission customer shall be determined in accordance with the following formula:—

$$MLTC = \{[(\text{Net ARR of the Transmission Licensee}/12) - 0.75 * STI - ITFI] / TCL_LT\} * CL$$

Explanation.—For the purpose of this regulation,—

- (a) “MLTC” means Monthly Long-Term Transmission Charge in Rs./month ;
- (b) “Net ARR” means Net Annual Revenue Requirement as determined in regulation 20 ;
- (c) “STI” means Income from Short-term customers of the transmission network, for the month, determined under sub-regulation (2) ;
- (d) “ITFI” means Income from provision for Intervening Transmission Facilities, for the month, determined under regulation 23 ;
- (e) “CL” means Contracted Capacity of the Transmission system by the Long-Term Transmission Customer;
- (f) “TCL_LT” means Total Contracted Capacity of the Transmission system by all Long-term Transmission Customers:

Provided that wherever it is necessary and expedient to incentivise the open access, the Commission may by order, cap the transmission charges calculated under this sub-regulation.

(2) Transmission charges payable by a Short-term Transmission Customer shall be calculated in accordance with the methodology as specified in the HPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005, namely :—

$$ST_RATE = 0.25 \times [TSC / Av_CAP] / 365$$

Explanation.—For the purpose of this sub regulation,—

- (a) “ST_RATE” means the rate for Short-term Customer in Rs per MW per day; and the “ST_RATE” shall be calculated and applied for transmission system of the State Transmission Utility or any other transmission licensee forming part of the intra-State transmission system;
- (b) “TSC” means the annual transmission charges or annual revenue requirement on account of the transmission system for the previous financial year as determined by the Commission;
- (c) “Av_CAP” means the average capacity in MW served by the intra-State transmission system of the transmission licensees in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other long term transactions handled by the system of the transmission licensees;

(3) The transmission charges payable by a short-term customer in case of uncongested transmission corridor shall be levied as under, namely :—

- (a) upto 6 hours in a day in one block = $\frac{1}{4}$ th of ST_RATE
- (b) more than 6 hours and upto 12 hours in a day in one block = $\frac{1}{2}$ of ST_RATE
- (c) more than 12 hours and upto 24 hours in a day in one block = ST_RATE;

(4) If the transmission system belongs to the State Transmission Utility, 25% of the charges collected from the short term customers for use of its intra-State system shall be retained by the State Transmission Utility and the remaining part of these charges shall be adjusted towards reduction in the transmission charges payable by the long term customers.

23. Charges for intervening transmission facilities.—(1) The rates and charges for intervening transmission facilities, if any, provided by the licensee shall be as mutually agreed upon between the licensee and the users of such facilities:

Provided that the rates and charges agreed upon shall be fair and reasonable and may be allocated in proportion to the use of the transmission facilities.

(2) Mutual agreement on these matters would be in the best interest of the parties. In case, such agreement cannot be reached within a reasonable period of time, either party shall be entitled to approach the Commission for determination under the proviso to sub-section (1) of section 36 of the Act and the Commission would expect evidence that negotiations were held in good faith and all reasonable efforts were made to arrive at a mutual agreement.

(3) The parties shall be at liberty to approach the Commission in case of any dispute regarding the extent of surplus capacity available, as provided for in section 35 of the Act.

(4) An application shall be made to the Commission for an Order requiring any other licensee owning or operating intervening transmission facilities to provide their use to the extent of surplus capacity available with it.

(5) After an order is passed under sub-regulation (4), read with section 35 of the Act, the concerned licensee shall provide his intervening transmission facilities at rates, charges and on terms and conditions as may be mutually agreed upon, under section 36 of the Act.

24. Applicability of charges for different users.—(1) The wheeling charges shall be applied uniformly to all users irrespective of location and quantum of energy transmitted.

(2) The transmission charges shall be applied uniformly to all users irrespective of location and quantum of power transmitted, depending upon the category of open access *i.e.* short term or long term.

25. Incentives on transmission charges.—(1) The transmission licensee shall, on achieving annual availability beyond the target availability as per regulation 10, be entitled to incentive in accordance with the following formula:—

$$\text{Incentive} = \text{Annual Transmission Charges} \times [\text{Annual availability achieved} - \text{Target Availability}] / \text{Target Availability};$$

Explanation.—For the purpose of this sub-regulation, no incentive shall be payable above the availability of 99.75% for Alternating Current (AC) system and 98.5% for High Voltage Direct Current (HVDC) system. Incentive shall be shared with the long-term transmission customers in the ratio of their average allotted transmission capacity for the year.

26. Transmission and distribution loss allocation.—The transmission and distribution loss allocation shall be as per the regulations specified in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge, Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006.

PART-III

STATE LOAD DESPATCH CENTRE FEES AND CHARGES

27. Levy and collection of fee and State Load Despatch Centre charges.—(1) The State Load Despatch Centre shall maintain its financial account separately and account all its expenses incurred, separately. If State Transmission Utility is operating the State Load Despatch Centre, the account related with the State Load Despatch Centre shall be maintained separately by the State Transmission Utility.

(2) The generating companies and licensees engaged in intra-State transmission of electricity, intending to get connected to the State Grid, shall submit an application to the State Load Despatch Centre in the specified format given in Annexure-“B” at least one month before the proposed date of connection to the State Grid, alongwith fee of Rs. One Lakh.

(3) The existing generating companies and licensees, engaged in intra-State transmission of electricity connected to the State Grid, shall register themselves with the State Load Despatch Centre, by filing an application alongwith the above-mentioned fees, within a month of coming into force of these regulations.

(4) The State Load Despatch Centre, after scrutinising the application and after being satisfied of the completeness and correctness of the information furnished in the application, shall register the application in the State Load Despatch Centre records duly intimating the applicant regarding the acceptance and file a copy with the Commission. The State Load Despatch Centre shall file information about the generating companies and licensees engaged in the intra-State transmission of electricity connected to the State Grid and being monitored/ serviced by them, to the Commission every year by the 15th November.

(5) The State Load Despatch Centre charges to be recovered from the generating companies and licensees engaged in intra-State transmission of electricity shall be determined taking

into account the expenses as detailed in regulation 11 and any other expenses incidental to discharging the functions of the State Load Despatch Centre.

(6) The short-term open access customer shall also pay to the State load Despatch Centre the operating charges as per the provisions of the Himachal Pradesh Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005.

28. Basis for collection of State Load Despatch Centre Charges.—The annual revenue requirement of the State Load Despatch Centre shall be arrived at in accordance with the annual revenue requirement calculations detailed in regulation 20 and shall first be divided into two equal parts – one to be recovered from the generating companies and the other from the licensees engaged in intra-State transmission of electricity. Thereafter, the allocation of charges to the individual generating companies shall be on the basis of installed generation capacity. The allocation of charges to individual licensees engaged in intra-State transmission of electricity shall be on the basis of the volume of energy wheeled through the transmission network.

29. Application for determination of fees and charges.—(1) Each year, by 30th November, the State Load Despatch Centre shall file with the Commission, an application / petition on the formats given in Annexure-C and also in accordance with the provisions, as specified by the Commission, in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005 for determination of fees and charges for the ensuing year.

(2) The application for 'Fees and Charges' recoverable by the State Load Despatch Centre shall be accompanied with an application fee of Rs. One Lakh.

(3) The State Load Despatch Centre must prepare an investment plan for a five-year period commencing with the ensuing financial year and must include the sources of funds for investment. The investment plan must be updated every year and filed with the Commission, alongwith the application specified under sub-regulation (1).

(4) If there is a revenue gap between the Expected Revenues from the currently applicable Fee and Charges and the revenue requirement for the ensuing financial year, the State Load Despatch Centre shall include a proposal as to how it proposes to bridge this revenue gap.

(5) The Commission may seek clarification and additional information on inadequacies in the application, if any, and the State Load Despatch Centre shall provide the clarification within the date stipulated by the Commission.

30. Information to generation companies and licensees engaged in intra-State transmission of electricity.—(1) After the Commission is provided with the clarifications, the State Load Despatch Centre shall provide copies of the complete application and further clarifications, if any, to the generating companies and the licensees engaged in intra-State transmission of electricity.

(2) The application for determination of 'fees and charges' should be posted at the State Load Despatch Centre website in downloadable format for easy accessibility by all stakeholders.

31. Hearing.—Unless for special reasons otherwise directed by the Commission, the Commission shall hold a proceeding on the revenue calculations and fee and charges proposals given

by the State Load Despatch Centre and may hear the generating companies and the licensees engaged in intra-State transmission of electricity or such persons as the Commission may consider appropriate for making a decision on such revenue calculations and fee and charges proposals.

32. Order of the Commission.—(1) The Commission shall analyse the petition submitted by the State Load Despatch Centre and assess the prudence of the costs and revenue items incurred or proposed to be incurred duly taking into account the petitioner's justifications, the objections to the petition and information from other sources, if sought by the Commission.

(2) The Commission, after completing all proceedings related to determination of fee and charges leviable by the State Load Despatch Centre, shall issue an Order within 120 days of the acceptance of the petition filed by the State Load Despatch Centre. The fees and charges so determined by the Commission shall come into force from the date as given in the Commission's Order and shall cease to operate, unless allowed to be continued for a further period with such variations or modifications, as may be ordered by the Commission.

33. Levy and collection of State Load Despatch Centre charges.—(1) The generating companies and the licensees shall pay to the State Load Despatch Centre, the annual charges in monthly instalments in advance.

(2) If the payment is not made within the due date, a penal interest at the rate of two percent per month shall be payable on the unpaid amounts.

(3) Disputes arising out of delay/non-payment of the State Load Despatch Centre Charges shall be, as far as possible, settled by mutual negotiations. If the disputes are not resolved through mutual negotiations within ninety days, the matter shall be referred to the Commission through a petition by either of the parties. The decision of the Commission shall be binding on both the parties.

34. Compliance with the directions by Transmission Licensee.—(1) Subject to the directions issued by the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre, the State Load Despatch Centre may, under sub-section (2) of section 32 and sub-section (1) of section 33, read with clause (b) of section 40 of the Act, give such directions as it may consider appropriate, for maintaining the availability of the transmission system and the transmission licensee shall duly comply with all such directions.

(2) The Commission, on an application filed by the State Load Despatch Centre and after hearing the transmission licensee, if satisfied that the transmission licensee has persistently failed to maintain the availability of the transmission system, may issue such directions to the State Load Despatch Centre to take control of the operations of the transmission system of such transmission licensee, for such period and on such terms, as the Commission may decide.

(3) The directions under sub-regulations(1) and (2) shall be without prejudice to any action which may be taken against the transmission licensee under other provisions of the Act.

PART -IV

MISCELLANEOUS

35. *Power to Amend.*—The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

36. *Power to remove difficulties.*—In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either *suo motu* or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

37. *Issue of orders and directions.*—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed for such implementation and matters incidental or ancillary thereto.

38. *Interpretation.*—All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

39. *Miscellaneous.*—(1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(3) Nothing in these regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission

Sd/-

Secretary

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Annexure - A
(See regulation 10)

Procedure for calculation of Transmission System Availability

- (1) Availability shall be calculated and declared separately for each voltage level.
- (2) The transmission elements shall be grouped into following categories for the purpose of calculation of availability of Transmission Systems:—
 - (a) AC transmission lines: Each circuit of AC transmission line shall be considered as one element.
 - (b) Inter-Connecting Transformers (ICTs): Each ICT bank (three single phase transformer together) shall form one element.
 - (c) Static VAR Compensator (SVC): SVC along with SVC transformer shall form one element. However, 50% credit to inductive and 50% to capacitive rating shall be given.
 - (d) Switched Bus Reactor: Each Switched Bus Reactor shall be considered as one element.
- (3) The Availability of AC Transmission system shall be calculated as under:—

% System Availability for AC system

$$\frac{o \times A_{vo} + p \times A_{vp} + q \times A_{vq} + r \times A_{vr}}{o + p + q + r} \times 100$$

Where

- | | | |
|----------|----|--|
| o | is | Total number of AC lines. |
| A_{vo} | is | Availability of o number of AC lines. |
| p | is | Total number of switched bus reactors. |
| A_{vp} | is | Availability of p number of Switched bus Reactors. |
| q | is | Total number of ICTs. |
| A_{vq} | is | Availability of q number of ICTs. |
| r | is | Total number of SVCs. |
| A_{vr} | is | Availability of r number of SVCs. |

(4) The weightage factor for each category of transmission elements shall be as under:—

- (a) For each circuit of AC line - Surge Impedance Loading for Uncompensated line (SIL) multiplied by Circuit Km. SIL rating for various voltage level and conductor configuration is given in Appendix-I. However, for the voltage levels and/or conductor configurations not listed in Annexure-I, appropriate SIL based on technical considerations may be used for availability calculation under intimation to long-term transmission customers.
- (b) For each ICT bank - The rated MVA capacity.
- (c) For SVC - The rated MVAR capacity (inductive & capacitive).
- (d) For Switched Bus Reactor - The rated MVAR capacity.

(5) The availability for each category of transmission elements shall be calculated based on the weight-age factor, total hours under consideration and non-available hours for each element of that category. The formulae for calculation of Availability of each category of the Transmission elements are as per Appendix-II.

(6) The transmission elements under outage due to following reasons not attributable to the Transmission Licensee shall be deemed to be available:

- (a) Shut down of transmission elements availed by other agency/agencies for maintenance or construction of their transmission system.
- (b) Manual tripping of line due to over voltage and manual tripping of Switched Bus Reactor as per the directions of RLDC / SLDC.

(7) Outage time of transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration:—

- (a) Outage of elements due to acts of God and force majeure events beyond the control of the Transmission Licensee.
- (b) Outage caused by grid incident/disturbance not attributable to the Transmission Licensee, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of the Transmission Licensee's elements, tripping of lines, ICTs, etc. due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from RLDC / SLDC while normalizing the system following grid incident/disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for whole period of outage and outage time shall be attributable to the Transmission Licensee.

(8) If the outage of any element causes loss of generation at the generating station, outage period for that element shall be deemed to be twice the actual outage period for the day(s) on which such of generation has taken place.

Appendix-I

[See para (4)(a) of Annexure-A]

SURGE IMPEDANCE LOADING (SIL) OF AC LINES

S.No.	Line voltage (kv)	Conductor Configuration	SIL (MW)
1.	400	Quad Bersimis	691
2.	400	Twin Moose	515
3.	400	Twin AAAC	425
4.	400	Quad Zebra	647
5.	400	Quad AAAC	646
6.	400	Tripple Snowbird	605
7.	400	ACKC(500/26)	556
8.	400	Twin ACAR	557
9.	220	Twin Zebra	175
10.	220	Single Zebra	132
11.	132	Single Panther	50
12.	66	Single Dog	10

Appendix-II

[See para (5) of Annexure-A]

FORMULAE FOR CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS

$$\text{Avo (Availability of o no. of AC lines)} = \frac{\sum_{i=1}^o \frac{W_i(T_i - T_{NAI})}{T_i}}{\sum_{i=1}^o W_i}$$

$$AV_q(\text{Availability of } q \text{ no. of ICTs}) = \frac{\sum_{k=1}^q \frac{W_k (T_k - T_{NAk})}{T_k}}{\sum_{k=1}^q W_k}$$

$$AV_r(\text{Availability of } r \text{ no. of SVCs}) = \frac{\left[\sum_{l=1}^r 0.5 \frac{W_{il} (T_{il} - T_{NAil})}{T_{il}} + \sum_{l=1}^r 0.5 \frac{W_{cl} (T_{cl} - T_{NACL})}{T_{cl}} \right]}{\left[\sum_{l=1}^r 0.5 W_{il} + \sum_{l=1}^r 0.5 W_{cl} \right]}$$

$$AV_s(\text{Availability of } s \text{ no. of Switched Bus Reactors}) = \frac{\sum_{m=1}^s \frac{W_m (T_m - T_{NAM})}{T_m}}{\sum_{m=1}^s W_m}$$

Where

W_i = Weightage factor for i^{th} transmission line

W_k = Weightage factor for k^{th} ICT

W_{il} & W_{cl} = Weightage factors for inductive & capacitive operation of for l^{th} SVC

W_m = Weightage factor for m^{th} bus reactor.

$T_i, T_k, T_{il}, T_{cl}, \& T_m$ = The total hours of i^{th} AC line, k^{th} ICT, l^{th} SVC (Inductive Operation), l^{th} SVC (Capacitive Operation) & m^{th} Switched Bus Reactor block during the period under consideration (excluding time period for outages not attributable to Transmission Licensee for reasons given in Para 7 of the procedure in annexure "A").

$T_{NAi}, T_{NAk}, T_{NAil}, \& T_{NACL}, T_{NAM}$ = The non-availability hours (excluding the time period for outages not attributable to Transmission Licensee taken as deemed availability as per Para 6 of the procedure in annexure "A") for i^{th} AC line, k^{th} ICT, l^{th} SVC (Inductive Operation), l^{th} SVC (Capacitive Operation) & m^{th} Switched Bus Reactor block.

Annexure-‘B’

[See regulation 27(2)]

**APPLICATION FOR REGISTRATION FOR CONNECTION WITH THE
STATE GRID**

Sl. No Particulars

1. Name of the Generating Company/ Licensee
2. Registered Address
3. Phone No./Fax/E-mail Id
4. Generating Capacity: In case of Generating Station Installed Capacity (in MWs)
5. Transmission Capacity: In case of Transmission Network the volume of energy handled (in MUs)
6. Proposed date of Connection with the State Grid
7. Details of Inter-connection point (enclose separate sheet if necessary)
8. DD No. and Date towards Registration Fee payable to State Load Despatch Centre
9. Undertaking:

We hereby undertake to abide by the instructions issued by the State Load Despatch Centre for Grid Management.

Signature of the Authorised Officer

Note.—The State Load Despatch Centre may prescribe and collect necessary technical details from the Generating Companies and Transmission Companies separately.

Annexure-C
[See regulation 29]

FORMATS FOR ARR & REVENUE FILING BY SLDC

	Summary Formats		
1.	Sheet	S1	Profit & Loss Account
2.	Sheet	S2	Balance Sheet
3.	Sheet	S3	Cash Flow Statement
4.	Sheet	S4	Annual Revenue Requirement
	Financial Formats		
5.	Sheet	F1	Revenue from Charges
6.	Sheet	F2	Project-wise / Scheme-wise Capital Expenditure
7.	Sheet	F3	Statement of Assets not in use
8.	Sheet	F4	Domestic loans, bonds and financial leasing
9.	Sheet	F5	R&M Expenses
10.	Sheet	F6	Employees' Cost & Provisions
11.	Sheet	F7	Administration & General Expenses
12.	Sheet	F8	Statement of Fixed Assets and Depreciation
13.	Sheet	F9	Interest & Finance Charges
14.	Sheet	F10	Details of Expenses Capitalised
15.	Sheet	F11	Other Debits
16.	Sheet	F12	Statement of Sundry Debtors and provision for bad and doubtful debts
17.	Sheet	F13	Extraordinary Items
18.	Sheet	F14	Net Prior Period Expenses/Income
	Schedule of Charges		
	Sheet	Schedule of Charges	Existing & Proposed Charges Schedule
Instructions for the Utility :			
1 Electronic copy in the form of CD/ Floppy Disc shall also be furnished			
These formats are indicative in nature and the utility may align the line items to its chart of			
2 accounts			
PY Previous Year			
CY Current Year			
EY Ensuing Year			

SLDC

Profit & Loss Account

Form No. S-1

(All figures in Rs Crore)

	Particulars	PY	CY	EY
		Actual	Estimated	Projection
A	Revenue			
1.	Revenue from charges			
2.	Other Income			
	Total Revenue or Income			
B	Expenditure			
1.	Repairs and Maintenance			
2.	Employee costs			
3.	Administration and General expenses			
4.	Net prior period credit charges			
5.	Other Debits, Write-offs			
6.	Extraordinary items			
7.	Less: Expenses Capitalized			
C	PBDIT(Profit before depreciation, interest and taxes)			
D	Depreciation and Related debits			
E	PBIT(Profit before depreciation, interest and taxes)			
1	Interest & Finance Charges			
2	Less: Interest Capitalized			
F	Total Interest and Finance Charges			
G	TOTAL EXPENDITURE			
H	Profit/Loss before Tax			
I	Income Tax			
J	Profit/Loss after Tax			

SLDC

Balance Sheet

Form No. S-2

(All figures in Rs. Crore)

Particulars	PY Actual	CY Estimated	EY Projection
I. SOURCES OF FUNDS			
<i>A) Shareholders' Funds</i>			
a) Share Capital			
b) Reserves and Surplus			
<i>B) Special Appropriation towards Project Cost</i>			
<i>C) Loan Funds</i>			
a) Secured Loans			
b) Unsecured Loans			
<i>D) Other sources of Funds</i>			
TOTAL SOURCES OF FUNDS			
II. APPLICATION OF FUNDS			
<i>A) Fixed Assets</i>			
a) Gross Block			
b) less: Accumulated Depreciation			
c) Net Block			
d) Capital Work in Progress			
e) less: Amount written off till date			
<i>B) Investments</i>			
<i>C) Current Assets, Loans and Advances</i>			
i) Current Assets			
ii) Loans & Advances			
<i>D) less: Current Liabilities and Provisions</i>			
i) Current Liabilities			
ii) Provisions			
<i>E) Net Current Assets</i>			
<i>F) Miscellaneous Expenditure to the extent not written</i>			
TOTAL APPLICATION OF FUNDS			

SLDC

Cash Flow Statement

Form No. S-3

(All figures in Rs. Crore)

Particulars		PY	CY	EY
		Actual	Estimated	Projection
I	Net Funds from Operations:			
1.	A. Net Funds from Earnings:			
	Profit before Tax			
	Less:			
	Income Tax payment during the year			
	Total of A			
	B. ADD: Debits to Revenue Account not requiring Cash Outflow:			
	(i) Depreciation			
	(ii) Amortisation of Deferred Cost			
	(iii) Amortisation of Intangible Assets			
	(iv) Investment Allowance Reserve			
	(v) Others, if any			
	Total of B			
	C. LESS: Credits to Revenue Account not involving Cash Receipts:			
	(i) Depreciation			
	(ii)			
	Total of C			
	Net Funds from Earnings (A+B-C)			
2.	Proceeds from disposal of Fixed Assets			
3.	Total Funds from Operations			
4.	Net Increase/(Decrease) in Working Capital:			
	A. Increase/(Decrease) in Current Assets:			
	(a) Inventories			
	(b) Receivables			
	(c) Loans and Advances			
	Total of A			
	B. Increase/(Decrease) in Current Liabilities:			
	(a) Borrowings for working capital			
	(b) - Others			
	Total of B			

Net Increase/(Decrease) in Working Capital (A - B)**Total I Net Funds from Operations****II Net Increase /(Decrease) in Capital Liabilities:****A. Fresh Borrowings:**

- (a) State Loans
- (b) Foreign currency Loans/Creditors
- (c) Other Borrowings

Total of A**B. Repayments:**

Repayment of Principal

- (a) State Loans
- (b) Foreign currency Loans/Creditors
- (c) Other Borrowings

Total of B**Total II Net Increase /(Decrease) in Capital Liabilities (A - B)****III Increase/(Decrease) in Equity Capital****IV Total Funds available for Capital Expenditure (I+II+III)****V Funds Utilised on Capital Expenditure:**

- (a) On Projects
- (b) Released Assets reissued to works
- (c) Intangible Assets
- (d) Deferred Costs

Total of V**VI Net Increase/(Decrease) in Investments****VII Net Increase/(Decrease) in Cash & Bank Balance (IV—V—VI)****VIII Add: Opening Cash & Bank balances****IX Closing Cash & Bank Balances (VII+VIII)**

SLDC

Form No. S-4

Annual Revenue Requirement

(All figures in Rs. Crore)

	Particulars		PY	CY	EY
			Actual	Estimated	Projection
1.	Receipts				
a	Revenue from charges				
b	Other Income				
	Total				
2.	Expenditure				
a	R&M Expense				
b	Employee Expenses				
c	A&G Expense				
d	Depreciation				
e	Interest & Finance Charges				
f	Less: Interest & other expenses capitalised				
g	Other Debits (incl. Provision for bad debts)				
h	Extraordinary Items				
I	Other (Misc.)-net prior period credit				
	Total				
3.	Annual Revenue Requirement				
4.	Surplus(+) / Shortfall (—) : before revision of charges				
5.	Impact Revision of Charges				
6.	Surplus(+) / Shortfall (—) : After Revision of Charges				

SLDC

Form No. F-1

Revenue from Charges				
		PY	CY	EY
Particulars		Revenue	Revenue	Revenue
		(Rs. in Cr.)	(Rs. in Cr.)	(Rs. in Cr.)
1. Licensee				
2.				
3.				
4. Generator				
5.				
6.				

Note.—This format should be filled as per the existing charges schedule.

SLDC

Project-wise / Scheme-wise Capital Expenditure (New Projects & CWIP)

Form No. F-2

Sl. No.	Particular	Project Cost		Reason for cost revision	Projected Schedule		Reasons for delay	Expenditure up to the end of preceding year	Expenditure during the year	Interest during Construction	Deductions/Transfers	Transfer to Fixed Assets	Source of Capital
		Original estimate	Revised estimate		Original completion date	Revised completion date						(Interest + expenses capitalized)	
	Financial Year*												
1													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

*Note.—Information to be provided for Previous Year, Current Year & Ensuing Year.

Statement of Assets Not in Use

Form No. F-3

(All figures in Rs. Crore)

[illegible]

*Note.—Information to be provided for Previous Year, Current Year & Ensuing Year

SLDC

Domestic loans, bonds and financial leasing

Form No. F-4

(All Figures in Rs.Crore)

[illegible]

3.	PFC											
4.	Bonds											th.
5.	Bank											
6.	APDRP											
7.	Any Other											
8.												
B	SHORT- TERM											
	Total											

*Note.—Loanwise information to be provided for Previous Year, Current Year & Ensuing Year.

SLDC

Repair & Maintenance Expenditure

Form No. F-5

(Figure in Rs. Crore)

Sl. No.	Particulars	PY	CY	EY
		Provisional	Estimate	Projection
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Total			

SLDC

Employee Cost and Provisions

Form No. F-6

		Particulars		PY	CY	EY
				Provisional	Estimate	Projection
A		Employee Strength				
		Working Strength at the Beginning of the Year				
		Employee Category				
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
		Total				
		Sanctioned Strength at the Beginning of the Year				
		Employee Category				
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
		Total				
B		Employee's Cost				
	1.	Salaries				
	2.	Dearness Allowance				
	3.	Other Allowances and Relief				
	4.	Medical Expenses Reimbursement				
	5.	Leave Travel Assistance				
	6.	Fee and Honorarium				
	7.	Incentives/Awards Including That in Partnership Project (Specify Items)				

	8.	Earned Leave Encashment				
	9.	Tuition Fee Re-imbursement				
	10.	Leave Salary Contribution				
	11.	Payment Under Workman's Compensation And Gratuity				
	12.	Subsidised Electricity to Employees				
	13.	Staff Welfare Expenses				
C		Apprentice and other Training Expenses				
D		Payment/Contribution to PF Staff Pension and Gratuity				
	1	Terminal Benefits				
		a) Provident Fund Contribution				
		b) Provision for PF Fund - Invested				
		Not Invested				
		c) Pension Payments				
		d) Gratuity Payment				
		e) Leave Encashment Payment				
	2	Any other items				
		Total D				
E		Bonus/Exgratia to Employees				
F		Grand Total				
G		Chargeable To Construction Works				
		Balance Item 'F' Appropriate For (F)-(G)				
		Relevant Indices of Wages Increase (As at the beginning and end of the Year)				
		WPI				
		CPI				
		D.A. rate				

SLDC

Form No. F-7

Adminstration & General Expenses

(All figures in Rs.crore)

Sl. No.	Particulars		Previous Year	Current Year	Ensuing Year
	In Rs. Crores		Provisional	Estimate	Projection
(A)	Administration Expenses				
1.	Rent rates and taxes (Other than all taxes on income and profit)				
2.	Insurance of employees, assets, legal liability				
3.	Telephone, Postage, Telegram, Internet Charges				
4.	Incentive and award to Employees/Outsiders				
5.	Consultancy Charges				
6.	Technical Fees				
7.	Other Professional Charges				
8.	Conveyance And Travel (vehicle hiring, running)				
9.	Security / Service Charges paid to Outside Agencies				
10.	Regulatory Expenses				
	Sub-Total of Administrative Expenses				
(B)	Other Charges				
1.	Fee and Subscriptions Books and Periodicals				
2.	Printing and Stationery				
3.	Advertisement Expenses (Other than purchase related) Exhibition & Demo.				
4.	Contributions/Donations to Outside Institute / Association				
5.	Electricity Charges to Offices				
6.	Water Charges				
7.	Any Study - As per requirements				
8.	Miscellaneous Expenses				
9.	Any other expenses				
10.	Legal Charges				
11.	Auditors Fee				
12.	Freight - Material Related Expenses				
	Total Charges				
	Total Charges Chargeable to Capital Works				
	Total Charges Chargeable to Revenue Expenses				

Form No. F-8

Fixed Assets and Provision for Depreciation (continues)

(All figures in Rs. Crore)

Provision Year

		Gross Fixed Assets				Provision For Depreciation				Net Fixed Assets		
Sl. No.	Particulars	At beginning of year	Addition during year	Adjustments & Deduction	At End of Year	Rate of Depreciation	At beginning of Year	Addition during Year	Adjustments & deduction	At end of Year	At the beginning of Year	At the end of Year
1.	Land & Land rights											
2.	Building and Civil Works											
	Others 1											
	Others 2											
	Others 3											
	Sub-Total											
3.	Communication equipment											
4.	Vehicles											
5.	Furniture & fixtures											
6.	Office Equipments											
7.	Assets taken over and pending final valuation											
8.	Any other Items											
	Total (1 to 8)											

Note.—1. Provide for fair value of assets if assessed.

Form No. F-8

Fixed Assets and Provision for Depreciation (continues)

(All figures in Rs. Crore)

Current Year

Sl. No.	Particulars	At beginning of year	Gross Fixed Assets			Provision For Depreciation				At end of Year	Net Fixed Assets	
			Addition during year	Adjustments & Deduction	At End of Year	Rate of Depreciation	At beginning of Year	Addition during Year	Adjustments & deduction		At the beginning of Year	At the end of Year
1.	Land & Land rights											
2.	Building and Civil Works											
	Others 1											
	Others 2											
	Others 3											
	Sub-Total											
3.	Communication equipment											
4.	Vehicles											
5.	Furniture & fixtures											
6.	Office Equipments											
7.	Assets taken over and pending final valuation											
8.	Any other items											
	Total (1 to 8)											

Note.—1. Provide for fair value of assets if assessed.

Form No. F-8

Fixed Assets and Provision for Depreciation (continues)*(All figures in Rs. Crore)***Current Year**

Sl. No.	Particulars	Gross Fixed Assets				Provision For Depreciation				At end of Year	Net Fixed Assets	
		At beginning of year	Addition during year	Adjustments & Deduction	At End of Year	Rate of Depreciation	At beginning of Year	Addition during Year	Adjustments & deduction		At the beginning of Year	At the end of Year
1.	Land & Land rights											
2.	Building and Civil Works											
	Others 1											
	Others 2											
	Others 3											
	Sub-Total											
3.	Communication equipment											
4.	Vehicles											
5.	Furniture & fixtures											
6.	Office Equipments											
7.	Assets taken over and pending final valuation											
8.	Any other items											
	Total (1 to 8)											

Note.—1. Provide for fair value of assets if assessed.

Form No. F-8

Fixed Assets and Provision for Depreciation (continues)

(All figures in Rs. Crore)

Ensuing Year

Sl. No.	Particulars	At beginning of year	Gross Fixed Assets			Provision For Depreciation				At end of Year	Net Fixed Assets	
			Addition during year	Adjustments & Deduction	At End of Year	Rate of Depreciation	At beginning of Year	Addition during Year	Adjustments & deduction		At the beginning of Year	At the end of Year
1.	Land & Land rights											
2.	Building and Civil Works											
	Others 1											
	Others 2											
	Others 3											
	Sub-Total											
3.	Communication equipment											
4.	Vehicles											
5.	Furniture & fixtures											
6.	Office Equipments											
7.	Assets taken over and pending final valuation											
8.	Any other items											
	Total (1 to 8)											

Note.—1. Provide for fair value of assets if assessed.

SLDC

Form No. 7

Interest & Finance Charges

(All figures in Rs. Crore)

		Particulars	Previous Year	Current Year	Ensuing Year
		In Rs. Crores	Actual	Projected	Projected
A	I	Interest and Finance Charges on Long Term Loans / Credits from the FIs/banks/organisations approved by the State Government			
		1. LIC			
		2. REC			
		3. PFC			
		4. Bonds			
		5. Bank/FIs			
		6. APDRP			
		7. Any other			
		Total of I			
	II	Interest on Working Capital Loans or Short Term Loans			
		Total of A : I + II			
B		Other Interest & Finance Charges			
		1. Cost of raising Finance & Bank Charges etc.			
		2. Penal Interest Charges			
		3. Lease Rentals			
		4. Penalty charges for delayed payment for power purchase			
		Total of B			
C		Grand Total of Interest & Finance Charges: A + B			
D		Less: Interest & Finance Charges Chargeable to Capital Account			
E		Net Total of Interest & Finance Charges : For Revenue Account: C-D			

SLDC

Details of Expenses Capitalised

Form No. F-10

(All figures in Rs Crore)

Sl. No.	Particulars		PY	CY	EY
			Actual	Estimated	Projection
1.	Interest & Finance charges Capitalised				
2.	Other expenses capitalised:				
	a. Employee expenses				
	b. R&M Expenses				
	c. A&G Expenses				
	e. Others, if any				
	Total of 2				
	Grand Total				

SLDC

Debits, Write-offs and any other items

Form No. -11

(All figures in Rs Crore)

Sl.No.	Particulars			PY	CY	EY
				Actual	Estimated	Projection
1.	Material Cost Variance					
2.	Miscellaneous Losses and Writte Off					
3.	Bad Debt Written Off/Provided For					
4.	Net Prior Period Credit/Charges					
	Sub-Total					
5.	Less Chargable to Capital Expense					
	Net Chargable to Revenue					

SLDC

Form No. F-72

Statement of Sundry Debtors and provision for bad & doubtful debts

(All figures in Rs. Crore)

Sl.No.	Particulars	PY	CY	EY
		Actual	Estimated	Projection
1.	Receivable from customers as at the beginning of the year			
2.	Revenue billed for the year			
3.	Collection for the year			
	Against current dues			
	Against arrears upto previous year			
4.	Gross receivable from customers as at the end of the year			
5.	Receivables			
6.	% of provision			
7.	Provision for bad and doubtful debts			

SLDC

Extraordinary Items

Form No. F-13

(All figures in Rs. Crore)

Sl.No.	Particulars	PY	CY	EY
		Actual	Estimated	Projection
1.	Extraordinary Credits(incl. subsidies aganst losses due to natural disasters			
	TOTAL CREDITS			
2.	Extraordinary Debits (incl. subsidies aganst losses due to natural disasters			
	TOTAL DEBITS			
	Grand Total			

SLDC

Form No. F-14

Net Prior Period Expenses / Income

Form No. F-14

Sl.No.	Particulars	PY	CY	EY
		Actual	Estimated	Projection
A	Income relating to previous years:			
1.	Interest income for prior periods			
2.	Income Tax proir period			
3.	Excess Provision for Depreciation			
4.	Excess Provision for Interest and Fin. Charges			
5.	Receipts from consumers			
6.	Other Excess Provision			
7.	Others Income			
	Sub-Total A			
B	Expenditure relating to previous years			
1.	Operating Expenses			
2.	Employee Cost			
3.	Depreciation			
4.	Interest and Finance Charges			
5.	Admn. Expenses			
6.	Withdrawal of Revenue Charges			
7.	Material Related			
8.	Other			
	Sub-Total B			
	Net prior period Credit/(Charges) : A-B			

6800

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 नवम्बर, 2006/18 कार्तिक, 1928

SLDC

Form: Schedule of Charges

Existing & Proposed Charges Schedule

		EXISTING TARIFFS			PROPOSED TARIFFS	
Sl. No.	User Type	Monthly Fixed Charge per Connection (Rs.)	Total Revenues		Monthly Fixed Charge per Connection (Rs.)	Total Revenues
1.	Licensee					
2.						
3.						
4.	Generator					
5.						
6.						
7.						